शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक

प्रकाशन का 50 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 50 अंक – 11 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 10 – 17 मार्च 2025 मूल्य पांच रूपये

सुखविंदर सिंह बनाम निशु ठाकुर एवं अन्य मानहानि मामले को प्रवीण कुमार ने दी उच्च न्यायालय में चुनौती

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2017 में जब वह नादौन से विधायक थे तब निशु ठाकुर, ईशा ठाकुर, प्रवीण कुमार पत्रकार अमर उजाला और कपिल बस्सी पत्रकार दैनिक सवेरा के खिलाफ आपराधिक एवं सिविल मानहानि के मामले शिमला तथा हमीरपुर में दायर किये थे। लेकिन इन मामलों का निपटारा अब तक नहीं हो सका है। हमीरपुर में दायर हुआ सिविल मामला अब शायद लोक अदालत में पहुंच गया है। शिमला में दायर हुये आपराधिक मामले में प्रतिवादियों को शायद अभी तक वांछित दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं हो पाये हैं। यह मामले इतना लम्बा क्यों हो रहे हैं। इस पर अब अमर उजाला के पत्रकार प्रवीण कुमार ने हिमाचल उच्च न्यायालय में दस्तक देकर इस मामले को बन्द किये जाने की गुहार लगाई है। यह मामले जब दायर हुये थे तब सुखविंदर सिंह सुक्खू नादौन से विधायक और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे परन्तु अब तो वह दो वर्षो से भी अधिक समय से प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में यह मामले तो अब तक निपट जाने चाहिये थे। परन्तु ऐसा हो नहीं पाया है। इसलिये इन मामलों की पृष्ठभूमि में जाना आवश्यक हो जाता है। स्मरणीय है की मानहानि के यह मामले ईशा ठाकुर और निशु ठाकुर द्वारा 2016 में हमीरपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता पर आधारित हैं। इस पत्रकार वार्ता में इन भाई बहन ने नादौन के जडोत गांव में मानखड्ड पर कार्यरत एक स्टोन क्रेशर और हॉट मिक्सिंग प्लांट में हो रही अवैधताओं पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया था। यह आरोप लगाया था कि क्रेशर के साथ लगती उनकी 27 कनाल जमीन पर यह क्रेशर लगाया गया है। यह मामला उच्च न्यायालय ने भी स्वत: संज्ञान में लिया था। एनजीटी के आदेश से यह स्टोन क्रेशर वहां से हटाया गया है। ऐसे में स्टोन क्रेशर को लेकर उठाये गये एतराज स्वत: ही अधारहीन हो जाते हैं। इन्हीं पत्रकारवार्तो में एक आरोप यह भी था कि सुक्खू ने 769 कनाल जमीन अपने भाई के नाम खरीदी है। जिसे बाद में अपने नाम करवा लिया गया। यह पत्रकार वार्ताएं शायद 2016 में हुई। परन्तु इसका संज्ञान 2017 में लेकर मानहानि के मामले दायर किये गये। यहीं पर यह उल्लेखनीय हो जाता है कि सुक्खू ने 2017 में नादौन में विधानसभा चुनाव लड़ा और वह जीत गये। चुनाव परिणाम के कुछ समय बाद इन्हीं भाई बहन के पिता बसन्त सिंह ठाकुर ने सुक्खू के चुनाव को यह कहकर उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी की सुक्खू ने चुनाव शपथ पत्र में संपत्ति को लेकर तथ्यों को छुपाया है। उच्च न्यायालय ने इस पर चुनाव याचिका तो स्वीकार नहीं की क्योंकि समय अवधि निकल गयी। परन्तु आरोपों को सक्षम आर्थोरिटी के पास उठाने को कहा और अर्थोरिटी को निर्देश दिये की इस पर शीघ्र कारवाई हो। उच्च न्यायालय के निर्देशों पर यह मामला एसपी हमीरपुर के कार्यालय में जांच के लिये आ गया। यहां ए. एस.पी. ने इस मामले की जांच की और तथ्य छुपाने के आरोपों को सही पाया। ए.एस.पी की जांच रिपोर्ट के बाद धारा 156(3) के तहत यह मामला ए .सी.जे .एम. की अदालत में नादौन में दायर हो गया। यहां अदालत ने फिर जांच करवाई और तथ्यों को सही पाया। परन्तु अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि इससे किसी को व्यक्तिगत लाभ हानि नहीं हुई है इसलिये चालान को रद्द कर दिया जाये और इस सिफारिश पर चालान रद्द हो गया और सुक्खू को राहत मिल गयी।

नादौन अदालत के फैसले को उच्चन्यायालय मे चुनौति दी गयी। इस पर जस्टिस राकेश कैंथला की एकल पीठ ने इस याचिका को तो अस्वीकार कर दिया लेकिन साथ यह भी कह दिया कि इसका मामले के गुण दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे स्पष्ट हो जाता है की संपत्ति संबंधी तथ्यों को छुपाने के आरोप को अलग से चुनौती दी जा सकती है। क्योंकि खरीदी गई जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है कि इसमें ताबे हुकुक बर्तनदारान है और साथ ही 316 कनाल से अधिक की खरीद लैण्ड सीलिंग एक्ट के प्रावधानों में भी आती है। इस परिदृश्य में अमर उजाला के पत्रकार द्वारा मानहानि के मामले का उच्च न्यायालय में चुनौती दिया जाना रोचक और गंभीर हो जाता है। क्योंकि इस तरह के राजस्व इन्द्राज वाली जमीन विलेज् कामन लैण्ड हो जाती है। जिसे न खरीदा जा सकता है न बेचा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में 2011 में राज्यों के मुख्य सचिवों को कड़े निर्देश जारी किये हुये हैं।

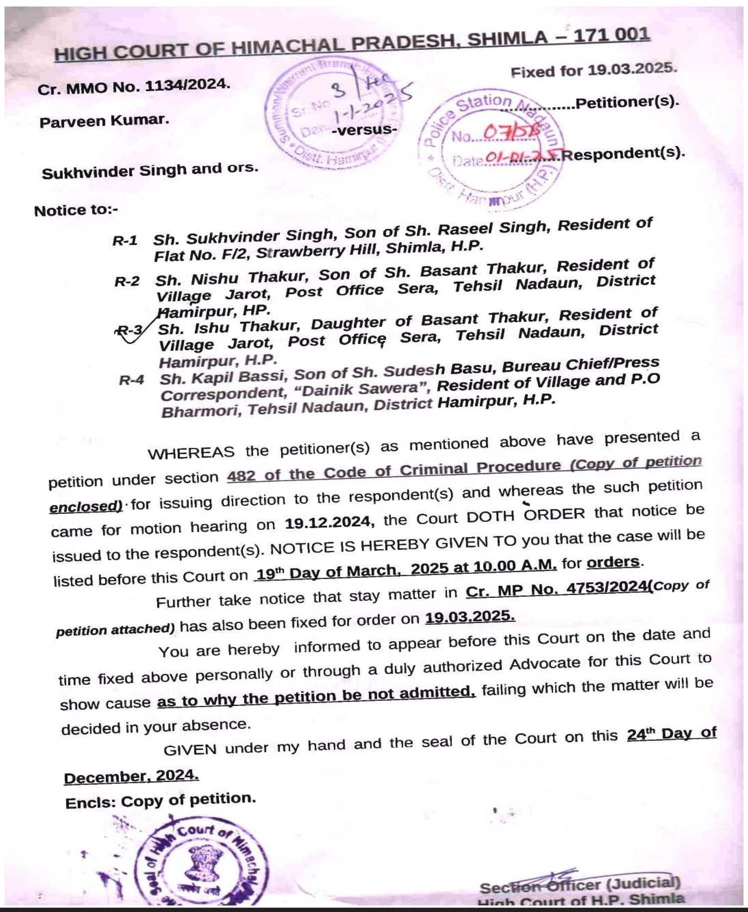

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

Cr. MMO No. 1134/2024. Fixed for 19.03.2025.

Parveen Kumar. ....Petitioner(s).

-versus-

Sukhvinder Singh and ors. ....Respondent(s).

Notice to:-

R-1 Sh. Sukhvinder Singh, Son of Sh. Raseel Singh, Resident of Flat No. F/2, Strawberry Hill, Shimla, H.P.

R-2 Sh. Nishu Thakur, Son of Sh. Basant Thakur, Resident of Village Jarot, Post Office Sera, Tehsil Nadaun, District Hamirpur, HP.

R-3 Sh. Ishu Thakur, Daughter of Basant Thakur, Resident of Village Jarot, Post Office Sera, Tehsil Nadaun, District Hamirpur, H.P.

R-4 Sh. Kapil Bassi, Son of Sh. Sudesh Basu, Bureau Chief/Press Correspondent, "Dainik Sawera", Resident of Village and P.O Bharmori, Tehsil Nadaun, District Hamirpur, H.P.

WHEREAS the petitioner(s) as mentioned above have presented a petition under section 482 of the Code of Criminal Procedure (Copy of petition enclosed) for issuing direction to the respondent(s) and whereas the such petition came for motion hearing on 19.12.2024, the Court DOTH ORDER that notice be issued to the respondent(s). NOTICE IS HEREBY GIVEN TO you that the case will be listed before this Court on 19th Day of March, 2025 at 10.00 A.M. for orders.

Further take notice that stay matter in Cr. MP No. 4753/2024(Copy of petition attached) has also been fixed for order on 19.03.2025.

You are hereby informed to appear before this Court on the date and time fixed above personally or through a duly authorized Advocate for this Court to show cause as to why the petition be not admitted, failing which the matter will be decided in your absence.

GIVEN under my hand and the seal of the Court on this 24th Day of December, 2024.

Encls: Copy of petition.

Section Officer (Judicial)
High Court of H.P. Shimla

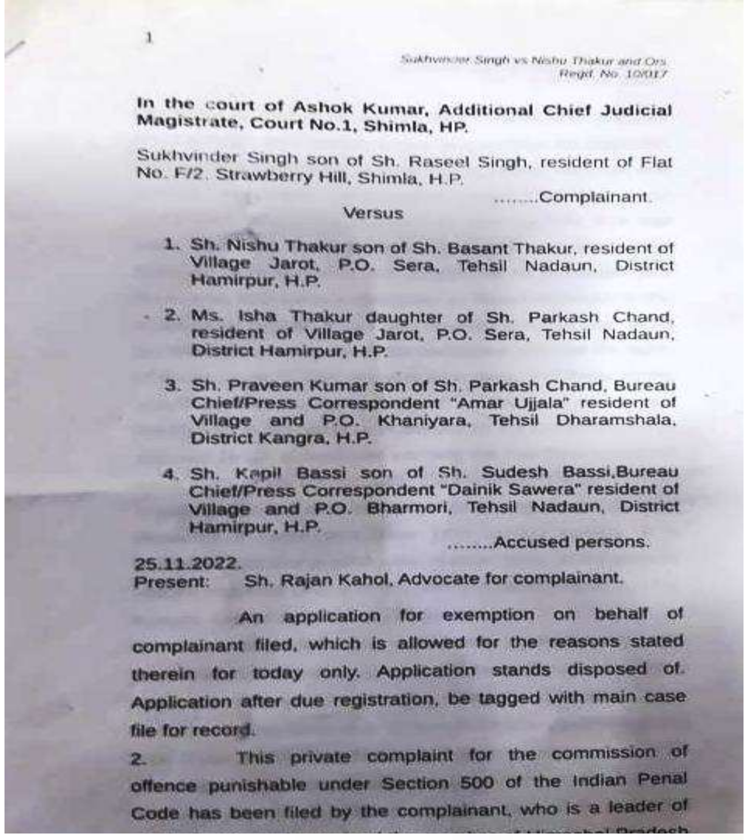

1

Sukhvinder Singh vs Nishu Thakur and Ors
Regd. No. 10/2017

In the court of Ashok Kumar, Additional Chief Judicial Magistrate, Court No.1, Shimla, HP.

Sukhvinder Singh son of Sh. Raseel Singh, resident of Flat No. F/2, Strawberry Hill, Shimla, H.P. ....Complainant.

Versus

1. Sh. Nishu Thakur son of Sh. Basant Thakur, resident of Village Jarot, P.O. Sera, Tehsil Nadaun, District Hamirpur, H.P.
2. Ms. Isha Thakur daughter of Sh. Parkash Chand, resident of Village Jarot, P.O. Sera, Tehsil Nadaun, District Hamirpur, H.P.
3. Sh. Praveen Kumar son of Sh. Parkash Chand, Bureau Chief/Press Correspondent "Amar Ujjala" resident of Village and P.O. Khaniyara, Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P.
4. Sh. Kapil Bassi son of Sh. Sudesh Bassi,Bureau Chief/Press Correspondent "Dainik Sawera" resident of Village and P.O. Bharmori, Tehsil Nadaun, District Hamirpur, H.P.

........Accused persons.

25.11.2022.
Present: Sh. Rajan Kahol, Advocate for complainant.

An application for exemption on behalf of complainant filed, which is allowed for the reasons stated therein for today only. Application stands disposed of. Application after due registration, be tagged with main case file for record.

2. This private complaint for the commission of offence punishable under Section 500 of the Indian Penal Code has been filed by the complainant, who is a leader of

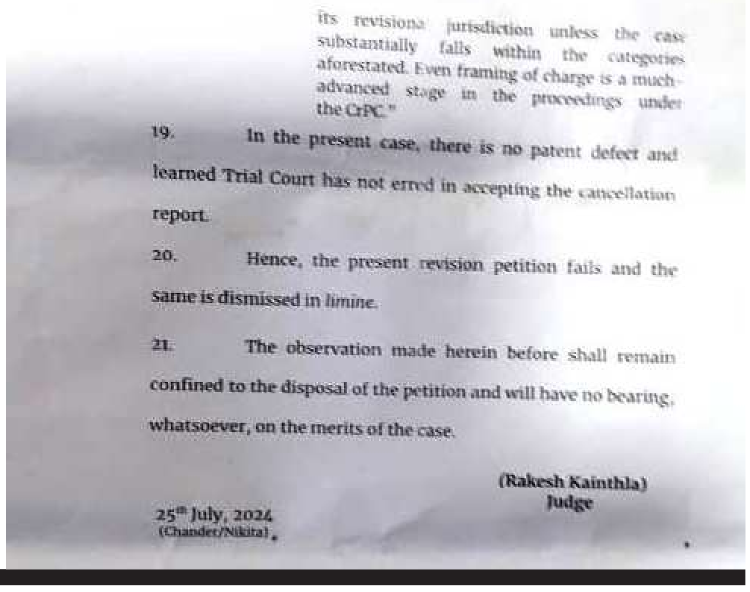

its revisional jurisdiction unless the case substantially falls within the categories aforestated. Even framing of charge is a much-advanced stage in the proceedings under the CrPC."

19. In the present case, there is no patent defect and learned Trial Court has not erred in accepting the cancellation report.

20. Hence, the present revision petition fails and the same is dismissed in limine.

21. The observation made herein before shall remain confined to the disposal of the petition and will have no bearing, whatsoever, on the merits of the case.

(Rakesh Kainthla)
Judge

25th July, 2024
(Chander/Nikita)

राजभवन में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन

शिमला/शैल। होली उत्सव के अवसर पर राजभवन में होली मिलन कार्यक्रम में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल

और लेडी गवर्नर जानकी शुक्ला ने भाग लिया और प्रदेश के लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अपनी धर्मपत्नी एवं विधायक कमलेश ठाकुर और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया के साथ राजभवन पहुंच कर राज्यपाल को होली की शुभकामनाएं दीं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी समारोह में शामिल हुए।

नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर अपनी धर्मपत्नी डॉ. साधना ठाकुर, अन्य भाजपा विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ राज्यपाल से मिले और होली की बधाई दी।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि होली उत्सव एकता, सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक है और लोग सभी मतभेदों को भुलाकर एक साथ मिलकर इस पर्व का मनाते हैं। उन्होंने कहा कि रंगों का यह पर्व देश और हिमाचल प्रदेश की एकता और अखण्डता का जीवंत प्रतीक है। देवभूमि के रूप में विख्यात हिमाचल में होली की अपनी एक समृद्ध परम्परा है।

राज्यपाल ने नशे की बुराई के खिलाफ चलाये जा रहे जन जागरूकता अभियान 'हिमाचल बचाओ, नशा भगाओ' पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि इस अभियान में गांवों के लोग बढ़-चढ़ कर भाग ले रहे हैं और होली की भावना के माध्यम से यह अभियान और मजबूत होगा। उन्होंने सभी से गरिमा और सद्भाव के साथ इस पर्व को मनाने का आहवान किया।

राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री ने होली उत्सव की बधाई दी

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल तथा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को होली उत्सव की शुभकामनाएं दी हैं।

शिव प्रताप शुक्ल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि रंगों के त्योहार होली का हमारी संस्कृति में विशेष महत्त्व है। उन्होंने आशा जताई कि यह त्योहार भाईचारे की भावना को सुदृढ़ कर देश की एकता तथा अखण्डता को और मज़बूती प्रदान करेगा।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अपने बधाई सन्देश में कहा कि होली उत्सव को हर संप्रदाय एवं धर्म के लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, जिससे सामाजिक सौहार्द को और मज़बूत बनाने में सहायता मिलती है।

राज्यपाल ने राष्ट्रस्तरीय होली उत्सव की शोभायात्रा में भाग लिया

शिमला/शैल। सुजानपुर का चार दिवसीय राष्ट्रस्तरीय होली उत्सव के समापन अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया तथा ऐतिहासिक मुरली मनोहर मंदिर में पूजा-अर्चना की।

इस अवसर पर उन्होंने चौगान में लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। उन्होंने सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वयं सहायता समूहों और अन्य संस्थाओं की प्रदर्शनियों की सराहना की।

इससे पहले, सुजानपुर पहुंचने पर राज्यपाल का भव्य स्वागत किया गया।

स्थानीय विधायक कैप्टन रणजीत सिंह, उपायुक्त एवं राष्ट्रस्तरीय होली उत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष अमरजीत सिंह, एसपी भगत सिंह ठाकुर, मेला अधिकारी एवं एसडीएम संजीत सिंह, मेला पुलिस अधिकारी एवं एएसपी राजेश कुमार, अन्य वरिष्ठ अधिकारियों, नगर परिषद के पदाधिकारियों और अन्य गणमान्य लोगों ने राज्यपाल का स्वागत किया।

निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रियाओं की मजबूती के लिए राजनीतिक दलों से सुझाव आमंत्रित किए

शिमला/शैल। भारत निर्वाचन आयोग के कानूनी ढांचे के भीतर चुनावी प्रक्रियाओं को और मजबूत करने के लिए सभी राष्ट्रीय और राज्यों के राजनीतिक दलों से 30 अप्रैल, 2025 तक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी या मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर किसी भी अनसुलझे मुद्दे के लिए, सुझाव आमंत्रित किए हैं। राजनीतिक दलों को जारी पत्र में आयोग ने स्थापित कानून के अनुसार चुनावी प्रक्रियाओं को और मजबूत करने के लिए पारस्परिक रूप से सुविधाजनक समय पर पार्टी के अध्यक्षों और वरिष्ठ सदस्यों के साथ बातचीत की भी परिकल्पना की है।

राज्य निर्वाचन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि ईसीआई सम्मेलन के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठक करने, बैठकों में प्राप्त किसी भी सुझाव को पहले से मौजूद कानूनी ढांचे के भीतर सख्ती से हल करने और 31 मार्च, 2025 तक आयोग को एक कारवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। आयोग ने राजनीतिक दलों से विकेंद्रीकृत जुड़ाव के इस तंत्र का सक्रिय रूप से उपयोग करने का भी आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि संविधान और वैज्ञानिक ढांचे के अनुसार चुनाव प्रक्रिया के सभी पहलुओं को कवर करने वाले आयोग द्वारा पहचाने गए 28 हितधारकों में से राजनीतिक दल प्रमुख हितधारकों में से एक हैं। राजनीतिक दलों को लिखे अपने पत्र में आयोग ने यह भी उल्लेख किया है कि जनप्रतिनिधित्व अनिनियम-1950 और 1951, मतदाता पंजीकरण नियम-1960, चुनाव संचालन नियम-1961, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और भारत के चुनाव आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देश, मैनुअल और हैंडबुक (ईसीआई वेबसाइट पर उपलब्ध) ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए विकेन्द्रीकृत, मजबूत और पारदर्शी कानूनी ढांचा स्थापित किया है।

उप-मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि यह त्योहार रंगों, प्यार और खुशी का प्रतीक है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि होली का यह पावन अवसर सभी के जीवन में खुशियां और समृद्धि लेकर आएगा।

उन्होंने कहा कि रंगों का यह त्योहर समाज में प्रेम, सौहार्द और एकता को बढ़ावा देता है और हम सभी को जिम्मेदारी से इस त्योहार को मनाना चाहिए।

फॉरेंसिक सेवाएं निदेशालय में जैविक नमूनों के संग्रह और संरक्षण पर कार्यशाला आयोजित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश फॉरेंसिक सेवाएं निदेशालय, जुन्गा, जिला शिमला ने डीएनए प्रोफाइलिंग और फॉरेंसिक विषाक्त विज्ञान के लिए जैविक नमूनों के संग्रह और संरक्षण पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन को किया। यह कार्यशाला प्रदेश के विभिन्न जिलों के चिकित्सा अधिकारियों के लिए आयोजित की गई, ताकि जैविक एवं भौतिक साक्ष्यों को डीएनए प्रोफाइलिंग और फॉरेंसिक टॉक्सीकोलॉजी के रासायनिक परीक्षण के लिए एकत्रित किए जा सके।

फॉरेंसिक सेवाएं निदेशलय के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में पिछले वर्ष आयोजित हिमाचल प्रदेश फॉरेंसिक विकास बोर्ड की बैठक में फॉरेंसिक विज्ञान से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई थी तथा यह कार्यशाला भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की गई।

निदेशक फॉरेंसिक सेवाएं डॉ. मीनाक्षी महाजन ने कार्यशाला के दौरान अपने संबोधन में कहा कि आज के युग में डीएनए की महता बहुत बढ़ गई है इसलिए चिकित्सा अधिकारियों द्वारा हत्या एवं बलात्कार जैसे संगीन मामलों में साक्ष्यों को एकत्रित एवं संरक्षित करके अन्वेषण अधिकारियों को सौंपना एक अहम जिम्मेदारी बन गई है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा अधिकारियों को जघन्य अपराधों से संबंधित मामलों में नवीनतम जानकारी होना आवश्यक है।

प्रवक्ता ने बताया कि राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में फॉरेंसिक की अलग-अलग विशिष्टताओं से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम समय-समय पर पुलिस अन्वेषण अधिकारियों, चिकित्सा अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों तथा नए भर्ती हुए जजों के लिए समय-समय पर आयोजित की जाती हैं ताकि अपराधिक जांच और न्यायायिक विज्ञान के मानकों की जानकारी दी जा सके।

उन्होंने जानकारी दी कि भारतीय नागारिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) कानून की धारा 176(3) के अनुसार जिन आपराधिक मामलों में 7 साल की सजा का प्रावधान है उनमें फॉरेंसिक विशेषज्ञों का घटना स्थल का दौरा और साक्ष्य एकत्रित करना आवश्यक कर दिया गया है। कार्यशाला में हिमाचल प्रदेश के चिकित्सा अधिकारियों को अपराध संबंधित बारिकियों से अवगत करवाया गया।

निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए 219.46 करोड़ रुपये का बजट मंज़ूर

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर की अध्यक्षता में बोर्ड के निदेशक मण्डल की 48वीं बैठक आयोजित की गई। बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश में निर्माण श्रमिकों के कल्याण एवं उत्थान के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 219.46 करोड़ रुपये के वार्षिक बजट को मंज़ूरी प्रदान की गई। बोर्ड के लाभार्थियों के उत्थान के लिए विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए 160 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

निर्माण कार्यों में कार्यरत बोर्ड के कामगारों के बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान के लिए कांगड़ा जिला के देहरा में एक डे-बोर्डिंग स्कूल की स्थापना के लिए 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष ने लाभार्थियों की रोजगार क्षमता बढ़ाने और बेहतर आजीविका के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए उनके कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर बल दिया। बैठक में सेवाओं में सुधार एवं उन्हें सुव्यवस्थित करने के लिए सभी लाभार्थियों के रिकार्ड को डिजिटल करने का भी निर्णय लिया गया। सूचना, शिक्षा और संचार पहल के तहत कामगारों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं अधिकारों से अवगत करवाने के लिए जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रमों को मंज़ूरी दी गई। प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए बोर्ड द्वारा हमीरपुर में कार्यालय के मरम्मत कार्यों को मंज़ूरी दी गई।

नरदेव सिंह कंवर ने सभी उपस्थित प्रतिभागियों को उनके बहुमूल्य योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बोर्ड राज्य में निर्माण श्रमिकों के कल्याण और उत्थान के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रहा है।

बैठक में बोर्ड के सदस्य रविंद्र सिंह रवि, भूपेंद्र सिंह, जे.सी. चौहान, हेमा तंवर, मुनीश करोल, ज्योति चौहान, अमर सिंह और नीलम गुप्ता उपस्थित थे।

विधान सभा अध्यक्ष की देश व प्रदेशवासियों को होली की बधाई

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां ने प्रदेश तथा देशवासियों को होली की बधाई देते हुए कहा कि होली भारत का एक अत्यंत प्राचीन पर्व है जो होली, होलिका या होलाका के नाम से जाना जाता है। बसंत ऋतु में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला रंगों का यह त्यौहार बसंतोत्सव और काम-महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। पहले दिन को होलिका जलायी जाती है जिसे होलिका दहन भी कहते हैं। दूसरे दिन जिसे प्रमुखतः धुलेंडी व धुरड्डी, धुरखेल या धूलिवंदन इसके अन्य नाम हैं लोग एक-दूसरे पर रंग अबीर-गुलाल इत्यादि फेंकते हैं तथा ढोल बजाकर होली के गीत गाते व एक-दूसरे को मिठाईयां भी बांटते हैं। राग-रंग का यह लोकप्रिय पर्व बसंत का संदेशवाहक भी है। उन्होंने कहा कि होली का त्यौहार सभी देश व प्रदेशवासियों के जीवन में अनेकानेक सफलताएं एवं अपार खुशियां लेकर आये।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादकःजे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकारः ऋचा शर्मा

सुजानपुर होली मेला हर्षोल्लास के साथ आरम्भ

शिमला/शैल। हमीरपुर जिला में 'चार' दिवसीय राष्ट्र स्तरीय सुजानपुर होली मेला हर्षोल्लास के साथ आरम्भ

हुआ। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सुजानपुर टीहरा स्थित ऐतिहासिक मुरली-मनोहर मंदिर में पूजा-अर्चना की और राज्य के लोगों की सुख-समृद्धि की प्राथना की।

इससे पहले, मुख्यमंत्री ने पगड़ी समारोह में भाग लिया और शोभा यात्रा का नेतृत्व किया। ऐतिहासिक चौगान मैदान से मुरली-मनोहर मंदिर तक सैकड़ों लोगों ने शोभा यात्रा में भाग लिया।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का शुभारम्भ किया। इनमें प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और हिम ईरा उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है।

सुजानपुर आगमन पर हजारों लोगों ने गर्मजोशी के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

मुख्यमंत्री ने होली के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह उत्सव एकता, सद्भाव और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सुजानपुर होली मेले में प्रदेश की समृद्ध संस्कृति की झलक देखने को मिलती है, साथ ही इससे आपसी भाईचारे को भी बल मिलता है।

मुख्यमंत्री ने सुजानपुर के लिए की जल शक्ति मंडल व ईसीएचएस अस्पताल की घोषणा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जिला हमीरपुर में राष्ट्र स्तरीय सुजानपुर मेले की पहली सांस्कृतिक संध्या की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस मेले की ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महता को देखते हुए इसे अन्तरराष्ट्रीय मेले का दर्जा प्रदान करेगी। उन्होंने सुजानपुर में जल शक्ति मंडल, ईसीएचएस अस्पताल और सुजानपुर अस्पताल में डायलसिस सुविधा स्थापित करने सहित सिन्थेटिक ट्रैक के निर्माण की घोषणा की।

लोगों को होली की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह सुजानपुर होली मेले में पहले भी आये थे और आज उन्हें खुशी महसूस हो रही है कि उनके द्वारा पूर्व में की गई घोषणाएं को पूरा करने के लिए तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है। सुजानपुर में 100 बिस्तरों के अस्पताल की अधिसूचना जारी कर दी गई है। आने वाले दो वर्षो में करोट में विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल बनकर तैयार हो जाएगा।

सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल को वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर बनाने और वर्ष 2032 तक देश का सबसे समृद्धशाली राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है।

सुजानपुर के विधायक कैप्टन रणजीत सिंह राणा ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सुजानपुर के विकास के लिए सभी क्षेत्रवासियों को एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सुजानपुर क्षेत्र में विकास और सुखद बदलाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले छः माह में क्षेत्र में विकास को गति मिली है और भविष्य में भी यहां की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान प्रदेश सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

मुख्यमंत्री ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में 43.64 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास किये

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हमीरपुर जिला के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 43.64 करोड़ रुपये की लागत की 10 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास किए।

उन्होंने करोट में 20.18 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले राजीव गांधी मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल का शिलान्यास किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने करोट ग्राम पंचायत में 1.42 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित सलघूण-घटा उठाऊ जल आपूर्ति योजना, 86 लाख रुपये की लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुठेड़ा के अतिरिक्त भवन एवं पुस्तकालय, 1.78 करोड़ रुपये की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सुजानपुर टिहरा में चिकित्सकों के लिए आवास, 1.42 करोड़ रुपये की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुजानपुर में पैरा-मेडिकल स्टाफ के लिए सरकारी आवास तथा 1.25 करोड़ रुपये की लागत से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पौंच में विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया।

मुख्यमंत्री ने 5.45 करोड़ रुपये की लागत से वार्ड नंबर-4 डोली में सुजानपुर बस अड्डा, 8.37 करोड़ रुपये की लागत से ग्राम पंचायत भेरड में बक्कर खड्ड से थलाम्बर गांव तक सम्पर्क मार्ग, 24 लाख रुपये की लागत से तहसील सुजानपुर के चबूतरा में विभिन्न गांवों के लिए उठाऊ जल आपूर्ति योजना तथा 2.67 करोड़ रुपये की लागत से नियुड़ से टिक्करी वाया धारली सम्पर्क मार्ग के शिलान्यास किए।

उन्होंने कहा कि ये विकासात्मक परियोजनाएं सुजानपुर क्षेत्र के लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में मीलपत्थर साबित होंगी।

विधायक कैप्टन रणजीत सिंह राणा ने विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने सुजानपुर सैनिक स्कूल में नए हॉस्टल के लिए 3 करोड़ रुपये देने की घोषणा की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हमीरपुर जिले के सुजानपुर टीहरा सैनिक स्कूल का दौरा किया तथा स्कूल परिसर में चल रहे मरम्मत कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को इन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

उन्होंने स्कूल के नए हॉस्टल के निर्माण के लिए तीन करोड़ रुपये देने और स्कूल के बजट में वृद्धि करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि स्कूल के ग्राउंड में सिंथेटिक ट्रैक की व्यवस्था की जाएगी।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सैनिक स्कूल के विद्यार्थियों की डाइट मनी को 10 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये तथा स्थानीय विधायक के माध्यम से स्कूल के लिए एंबुलेंस का प्रावधान भी किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सुजानपुर सैनिक स्कूल की आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने रखी थी और सुजानपुर के विकास में कांग्रेस की सरकारों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।

प्रधानाचार्य ग्रुप कैप्टन रचना जोशी और अन्य अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया तथा स्कूल की विभिन्न मांगों से अवगत करवाया।

डेंटल कॉलेज शिमला में स्थापित हुई (सीबीसीटी) यूनिट:स्वास्थ्य मंत्री

शिमला/शैल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ.(कर्नल) धनीराम शांडिल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राजकीय डेंटल महाविद्यालय एवं अस्पताल शिमला में कोन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी (सीबीसीटी) यूनिट स्थापित की गई है। यह सीबीसीटी यूनिट अत्याधुनिक रेडियोग्राफिक निदान उपकरण है जो राज्य में अपनी तरह का एकमात्र है। उन्होंने कहा कि इस उपकरण से समस्त जबड़ा एवं मैक्सिलोफेशियल क्षेत्र को सबसे बड़ी कवरेज प्रदान होती है।

उन्होंने कहा कि यह यूनिट थ्रीडी प्रक्षेपण से डेंटल और मैक्सिलोफेशियल हड्डी विकृति का निदान करने में सहायक सिद्ध होगी। टू.डी. एक्सरे की तुलना में यह उपकरण थ्री.डी. प्रक्षेपण बेहतर निदान क्षमता उपलब्ध करवाता है। उन्होंने कहा कि मेडिकल सीटी की तुलना में यह उपकरण बहुत कम विकिरण से हाई रिज़ॉल्यूशन से बेहतर परिणाम उपलब्ध करवाता है।

मंत्री ने कहा कि डेंटो-मेक्सिलोफेशियल निदान में यह मशीन व्यापक रूप से सहायक साबित होगी। इससे इंट्रा-ऑसियस प्रत्यारोपण, जटिल मैक्सिलो फैशियल फैक्चर, अस्थि विकृतियों का मूल्यांकन, जबड़े की हड्डियों से सम्बन्धित मुंह के कैंसर का मूल्यांकन, ऑरोफैशियल दर्द वाले मरीजों का मूल्यांकन, दंत पुनर्वास ईएनटी मूल्यांकन, स्लीप एपनिया वाले रोगियों में वायुमार्ग का विश्लेषण, मेडिकल फोरेंसिक और बेहतर रीस्टोरेटिव और प्रोस्थेटिक उपचार प्रदान करने के लिए दंत चिकित्सा में विस्तृत और बेहतर मूल्यांकन की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का यह प्रयास लोगों को दंत चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने में सहायक साबित होगा।

राजेश धर्माणी ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री से भेंट की

शिमला/शैल। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने नागपुर में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग

मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की। इस अवसर पर आयोजित बैठक में उन्होंने केंद्रीय मंत्री से सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग और लम्बित सड़क परियोजनाओं के बारे में विस्तृत चर्चा की।

नितिन गडकरी ने प्रदेश में पर्यटन आधारित बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने सहित विभिन्न विषयों पर विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कनेक्विटी को सशक्त करने के लिए रोपवे आधारित परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

बैठक में लुहणू से बेरी-दरोला तक पुल बनाने के मामले पर भी विचार-विमर्श किया गया। इस अवसर पर राज्य में आर्थिक विकास और पर्यटन गतिविधियों को सशक्त करने के लिए आधारभूत संरचना और सड़क नेटवर्क को मजबूत करने पर विशेष बल दिया गया। राजेश धर्माणी ने प्रदेश में अब तक स्वीकृत राष्ट्रीय राजमार्गों और रोपवे निर्माण के उदार वित्त पोषण के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया।

राज्य एड्स नियंत्रण समिति की बैठक में गैर-सरकारी संगठनों के कार्यों पर चर्चा

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति की मासिक बैठक परियोजना निदेशक राजीव कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में समिति के अंतर्गत कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए जा रहे कार्यों पर चर्चा करने के साथ-साथ राज्य में इंजेक्टिंग ड्रग के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की गई। उन्होंने कहा कि गैर-सरकारी संगठनों द्वारा इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स को साकियाट्रिक विभाग में नियमित रूप से रेफर करना एक सकारात्मक कदम हो सकता है। उन्होंने कहा कि हर जिले में साकियाट्रिक विभाग हैं जहां नशे की लत से जूझ रहे लोगों का उपचार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि नियमित जांच और ड्रग्स की लत को छोड़ने में मदद करने के लिए काउंसलिंग और थैरेपी बहुत मददगार साबित हो रहे हैं। वहीं, मनोवैज्ञानिक परामर्श से इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स की सोच में सकारात्मक बदलाव आता है और धीरे-धीरे ड्रग्स पर निर्भरता को कम किया जाता है। उन्होंने कहा कि इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह समान्य जीवन की ओर लौट सकते हैं।

राजीव कुमार ने कहा कि गैर-सरकारी संगठनों और साकियाट्रिक विभाग का आपसी समन्वय और सहयोग इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स के जीवन में परिवर्तन लाने में अहम भूमिका निभा सकता है।

उन्होंने सभी गैर-सरकारी संगठनों को निर्देश दिए कि सप्ताह में न्यूनतम पांच इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स को साकियाट्रिक विभाग में रेफर करें। इस दौरान गैर-सरकारी संगठनों का स्टाफ साथ में रहे और उनके स्वास्थ्य पर निरंतर निगरानी सुनिश्चित की जाए।

किसी भी समाज की सच्ची पहचान इस बात से होती है कि वह अपने सबसे कमजोर सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करता है। ...... महात्मा गांधी

सम्पादकीय

क्या शिक्षा और स्वास्थ्य में प्राईवेट सैक्टर का दखल होना चाहिये

क्या शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में निजी क्षेत्र का दखल होना चाहिये? यह सवाल इसलिये प्रसांगिक है क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य रोटी, कपड़ा और मकान के बाद महत्वपूर्ण बुनियादी आवश्यकता बन जाती हैं। कल्याणकारी राज्य व्यवस्था में हर नागरिक के लिये इन मूल आवश्यकताओं को उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। इन्हें पूरा करने के लिये केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक ने कई योजनाएं शुरू कर रखी हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने आयुषमान भारत योजना में 70 वर्ष से अधिक की आयु वाले बुजुर्गों को पांच लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान कर रखी है। राज्य सरकार ने भी कैंसर के रोगियों के लिये मुफ्त इलाज की घोषणा कर रखी है। अस्पताल में इन योजनाओं का लाभ लेने के लिये इतनी औपचारिकताएं लगा दी गयी हैं कि जब तक मरीज के साथ दो तामीरदार न हों तब तक इन योजनाओं का लाभ रोगी को नहीं मिल सकता। इसलिये इन औपचारिकताओं को जब तक हटाया या सरल नहीं किया जाता है तब तक इनका व्यवहारिक लाभ मिलना कठिन है। इसी के साथ इसका दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है कि अस्पताल में रोगी को मुफ्त में दी जा रही इन दवाईयों और अन्य उपकरणों को सरकार प्राइवेट सैक्टर से खरीद रही है। यह खरीद ही अपने में एक बड़ा घपला बनती जा रही है। क्योंकि प्राईवेट सप्लायर अस्पतालों को यह दवाईयां उस समय अंकित मूल्य के आधार पर दे रहा है। पिछले दिनों कैंसर रोगी को लिखी गयी एक दवाई कि उस पर्ची पर अंकित कीमत 2163 थी। अस्पताल को वह 2163 रूपये में स्पलाई हुई है लेकिन जब उसी दवाई को प्राईवेट मार्किट में कैमिस्ट से खरीदा गया तो उसने 2163 रूपये की दवाई 400 रूपये में दी। अस्पताल से ही दी गयी एक अन्य दवाई को जब बाजार में कैमिस्ट को दिखाया गया तो उसने उस दवाई को नकली करार दे दिया। जब यह सब सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को बताया गया तो उसने स्वीकार किया कि यह सब हो रहा है। और इसे कई बार सरकार के संज्ञान में भी लाया जा चुका है। लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। सप्लायर और कीमतों का फैसला प्रशासनिक स्तर पर होता है डॉक्टर के स्तर पर नहीं। पिछले दिनों प्रदेश के प्राईवेट अस्पतालों पर सीबीआई की छापेमारी हो चुकी है। आरोप सरकारी योजनाओं की आपूर्ति में हो रही है घपलेबाजी का ही था। हिमाचल का बद्दी सबसे बड़ा दवा निर्माण का केंद्र है। यहां बन रही कई दवाइयां के सैंपल कई बार फेल हो चुके हैं। सरकार हर बार संबंधित कंपनी को नोटिस थमाने की कारवाई से आगे नहीं बढ़ी है। दवाई का सैंपल फेल होने पर कितनी निर्माता कंपनियों पर आपराधिक कारवाई के तहत सजा हुई है इसका कोई आंकड़ा आज तक सामने नहीं आया है। जब दवाई का सैंपल फेल होने की रिपोर्ट सामने आ जाती है परंतु उस पर हुई कारवाई की रिपोर्ट सामने नहीं आती है। स्वभाविक है कि इन नकली दवाईयां की सप्लाई सरकार से लेकर प्राइवेट अस्पतालों तक में हो रही है। अस्पतालों में डॉक्टर इलाज के नाम पर मरीजों से कैसे व्यवहार कर रहे हैं यह राज्यसभा में अहमदाबाद के म्युनिसिपल अस्पताल के डॉक्टर के किस्से की चर्चा में सामने आ चुका है। डॉक्टर मरीज को आयुषमान कार्ड का लाभ तक देने को तैयार नहीं था। जब तक कि वह अपना पैर नहीं कटवा लेता। पैर न कटवाने पर डॉक्टर ने मरीज से 35000 रुपए नगद जमा करवाने को कहा। उसे आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं दिया। प्राईवेट अस्पतालों के इस तरह के कई मामले आये दिन चर्चा में आते रहते हैं। अहमदाबाद का यह मामला राज्यसभा तक पहुंच जाने पर यह सवाल उठता है कि आखिर इसका हल क्या है। कोविड काल में हुये टीकाकरण पर अब जो रिपोर्ट सामने आयी है उसके मुताबिक हर तीसरा आदमी इससे प्रभावित हुआ है। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक 45% सर्जरी अवांछित हो रही है। यह सब इसलिये हो रहा है कि स्वास्थ्य क्षेत्र के दरवाजे प्राईवेट सैक्टर के लिये खोल दिये गये हैं। वहां पर इलाज के नाम पर मरीज को लूटने का काम हो रहा है क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति हर व्यक्ति चिन्तित रहता है। प्राईवेट सैक्टर के लिये यह बहुत बड़ा व्यापार बन गया है। इसके परिणाम कालान्तर में बहुत भयानक होंगे। इसलिए स्वास्थ्य में प्राईवेट सैक्टर के दखल पर गंभीरता से एक सार्वजनिक बहस होनी चाहिये। शिक्षा पर अगले अंक में चर्चा होगी।

पर्वतमाला: राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम

देश में पहली बार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर जैसे क्षेत्रों के लिए पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। यह योजना पहाड़ों पर परिवहन और संपर्क की एक आधुनिक प्रणाली विकसित करेगी। इससे हमारे देश के सीमावर्ती गांवों को भी मजबूती मिलेगी, जिन्हें जीवंत बनाये रखने की आवश्यकता है। यह देश की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। - नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री-

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम-पर्वतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड में दो प्रमुख रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब जी तक 12.4 किलोमीटर लंबे रोपवे को 2,730.13 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जाएगा, जबकि सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबे रोपवे को 4,081.28 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी गई है। दोनों परियोजनाओं को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) ढांचे में डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) मॉडल के तहत निष्पादित किया जाएगा।

पर्वतमाला – एक सुरक्षित और कुशल वैकल्पिक परिवहन

पहाड़ी क्षेत्रों में कुशल परिवहन नेटवर्क विकसित करना एक बड़ी चुनौती है। इन क्षेत्रों में रेल और हवाई परिवहन नेटवर्क सीमित हैं, जबकि सड़क नेटवर्क के विकास में काफी तकनीकी चुनौतियां हैं। इस हालात में रोपवे एक सुविधाजनक और सुरक्षित वैकल्पिक परिवहन मोड के रूप में उभरा है।

सुदूर और पहाड़ी क्षेत्रों में अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी (संपर्क) बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 2022 के बजट में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम-पर्वतमाला की घोषणा की थी। नैशनल हाइवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड (एनएचएलएमएल) द्वारा कार्यान्वित इस पहल का लक्ष्य पांच वर्षों के भीतर 1,200 किलोमीटर तक 250 से अधिक रोपवे परियोजनाएं विकसित करना है, जो पारंपरिक सड़क परिवहन के लिए एक सतत और कुशल विकल्प प्रदान करेगा।

'मेक इन इंडिया' पहल के तहत इस कार्यक्रम में रोपवे निर्माण में कम से कम 50% स्वदेशी पुर्जो का उपयोग अनिवार्य किया गया है। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव के साथ रोपवे परियोजना भारत के चुनौतीपूर्ण इलाकों के लिए लागत प्रभावी, ऊर्जा कुशल और विश्वसनीय परिवहन समाधान प्रदान करेंगे।

रोपवे के बुनियादी ढांचा को संचालित करने वाले प्रमुख कारक

1. **किफायती** – रोपवे बनाने के लिए न्यूनतम भूमि की आवश्यकता होती है, जिससे भूमि अधिग्रहण की लागत कम हो जाती है। सड़कों की तुलना में प्रति किलोमीटर निर्माण लागत अधिक होने के बावजूद रखरखाव लागत में कमी आने के कारण रोपवे समग्र रूप से अधिक किफायती हो सकते हैं।

2. **तेज गति** – रोपवे हवाई मार्ग प्रदान करते हैं, जिससे वे पहाड़ी और चुनौतीपूर्ण इलाकों को तेजी से पार करते हैं।

3. **पर्यावरण अनुकूल** – रोपवे में धूल उत्सर्जन कम होता है और साथ कंटेनरों को इस तरह डिजाइन किया जा सकता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में मदद मिले।

4. **दूरदराज के क्षेत्रों से संपर्क** – रोपवे परियोजनाएं यात्रियों के बड़े पैमाने पर आवागमन को सक्षम बनाती हैं, और लास्ट माइल कनेक्टिविटी का कुशल समाधान प्रदान करती हैं।

व्यापकता: व्यापक कार्यान्वयन : उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे राज्यों को कवर किया गया।

शहरी और ग्रामीण संपर्क बनाने पर जोर : ग्रामीण क्षेत्रों और पर्यटन स्थलों में दैनिक आवागमन को सहायता प्रदान करना है।

भीड़भाड़ कम करना : भीड़भाड़ वाले स्थानों में वैकल्पिक परिवहन साधन उपलब्ध कराना है।

रोजगार के अवसर : निर्माण, संचालन और रखरखाव जैसे क्षेत्रों में रोजगार सृजित होते हैं।

आर्थिक विकास: स्थानीय व्यवसायों और संबद्ध उद्योगों को मजबूती प्रदान करना है।

रोपवे के लाभ:

कठिन/ चुनौतीपूर्ण/ संवेदनशील इलाके के लिए आदर्श: परिवहन का यह साधन दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आवागमन में सक्षम बनाएगा तथा उन्हें मुख्यधारा का हिस्सा बनने में मदद करेगा।

अर्थव्यवस्था: रोपवे जिसमें एक ही पावर-प्लांट और ड्राइव मैकेनिज्म द्वारा संचालित कई कारें हैं। यह निर्माण और रखरखाव लागत, दोनों को कम करता है। पूरे रोपवे के लिए एक ही अ परेटर का उपयोग श्रम लागत में एक और बचत करता है।

लचीला: रोपवे विभिन्न प्रकार की सामग्री के एक साथ परिवहन की सुविधा प्रदान करता है।

बड़ी ढलानों को संभालने की क्षमता: रोपवे और केबल-वे (केबल क्रेन) बड़े ढलानों और ऊंचाई में बड़े अंतर को संभाल सकते हैं। जहां किसी सड़क या रेलमार्ग को स्विचबैक या सुरंगों की आवश्यकता होती है, रोपवे सीधे ऊपर और नीचे फॉल लाइन की यात्रा करता है।

कम ज़मीन की ज़रूरत : तथ्य यह है कि अंतराल पर केवल संकरे-आधारित लंबवत समर्थन की आवश्यकता होती है, शेष जमीन को मुक्त छोड़कर, निर्मित क्षेत्रों में और उन जगहों पर जहां भूमि उपयोग के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा होती है, रोपवे के निर्माण को संभव बनाता है।

केदारनाथ रोपवे परियोजना

राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम - पर्वतमाला परियोजना के तहत 4,081.28 करोड़ रुपये की लागत से सोनप्रयाग-केदारनाथ रोपवे परियोजना (12.9 किमी) को मंजूरी दी गई है। इसे उन्नत ट्राई-केबल डिटैचेबल गोंडोला (3एस) प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विकसित किया जाएगा, जिसकी क्षमता प्रति घंटे प्रत्येक दिशा में 1,800 यात्रियों की होगी। रोपवे से यात्रा का समय 8-9 घंटे से घटकर मात्र 36 मिनट रह जायेगा, जिससे केदारनाथ तीर्थयात्रियों को सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल तथा सभी मौसमों में आवागमन की सुविधा मिलेगी। इस परियोजना से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और आतिथ्य एवं यात्रा जैसे स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ में हर साल करीब 20 लाख तीर्थयात्री आते हैं और इस परियोजना से इस पवित्र तीर्थस्थल तक पहुंच और आसान हो जाएगी।

हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना

गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब जी तक रोपवे सभी मौसम में संपर्क प्रदान करेगा साथ ही आधुनिक परिवहन प्रणाली के साथ चुनौतीपूर्ण 21 किलोमीटर की यात्रा समाप्त हो जाएगी। इसमें गोविंदघाट से घांघरिया (10.55 किमी) तक मोनोकेबल डिटैचेबल गोंडोला (एमडीजी) और घांघरिया से हेमकुंड साहिब जी (1.85 किमी) तक 1,100 यात्रियों प्रति घंटे की क्षमता के साथ ट्राइकेबल डिटैचेबल गोंडोला (3 एस) की सुविधा होगी, जिसमें प्रतिदिन 11,000 यात्रियों को ले जाया जा सकेगा। 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब जी में प्रतिवर्ष 1.5 से 2 लाख तीर्थयात्री आते हैं और यह फूलों की घाटी (यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल) के नजदीक है। इस परियोजना से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार सृजित होंगे तथा क्षेत्र के आर्थिक विकास को सहायता मिलेगी।

पर्वतमाला परियोजना के तहत प्रमुख रोपवे परियोजनाएं

रोपवे प्रौद्योगिकी संपर्क व्यवस्था को बढ़ाती है। पर्यटन को बढ़ावा देती है और लागत प्रभावी व भूमि कुशल होने के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी सृजित करती है। नदियों, इमारतों, खड्डों या सड़कों जैसी प्राकृतिक बाधाओं को पार करके रोपवे पारंपरिक बुनियादी ढांचे के लिए एक व्यावहारिक विकल्प प्रदान करते हैं। पर्वतमाला परियोजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 तक 60 किलोमीटर की परियोजनाएं प्रदान करने की योजना है। इसके लिए उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम और महाराष्ट्र सहित 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

निर्माणाधीन रोपवे परियोजनाए:

वाराणसी शहरी रोपवे: भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों में परिवहन के वैकल्पिक साधन के रूप में रोपवे का भी विकास किया जा रहा है। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी में भारत की पहली शहरी रोपवे परियोजना की आधारशिला रखी गई, जो वाराणसी कैंट से निर्माणाधीन है। वाराणसी की व्यस्त सड़कों पर भीड़भाड़ कम करने के लिए डिजाइन की गई इस परियोजना में 148 गोंडोला केबिन होंगे, जो प्रतिदिन 96,000 यात्रियों का परिवहन करने में सक्षम होंगे। रोपवे से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और यात्रा का समय कम होगा, जिससे शहर के लिए आधुनिक, कुशल और पर्यावरण अनुकूल परिवहन समाधान उपलब्ध होगा। वाराणसी के चुनौतीपूर्ण परिदृश्य में इस 3.85 किलोमीटर खंड का विकास भारत के शहरी बुनियादी ढांचे में उन्नत रोपवे प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

गौरीकुंड-केदारनाथ रोपवे (9.7 किमी, 3,584 मीटर ऊंचाई): इस परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि, ट्राई-केबल डिटेचेबल गोंडोला के साथ यात्रा का समय वर्तमान 7 से 9 घंटे से घटकर केवल 28 मिनट रह जाएगा, जो प्रति घंटे प्रत्येक दिशा में 3600 यात्रियों को ले जाएगा।

आगामी एवं स्वीकृत रोपवे परियोजनाएं:

स्वीकृत परियोजनाएं (4.93 किमी लंबाई)

बिजली महादेव (हिमाचल प्रदेश)
धोसी हिल (हरियाणा),
महाकालेश्वर मंदिर (मध्य प्रदेश)।

पसंदीदा बोलीदाताओं की पहचान की गई (3.25 किमी लंबाई)

संगम प्रयागराज (उत्तर प्रदेश),
शंकराचार्य मंदिर (जम्मू-कश्मीर)।

7 परियोजनाओं के लिए बोलियां आमंत्रित की गई (कुल 53.28 किमी)

सोनप्रयाग-केदारनाथ (उत्तराखंड)
गोविंदघाट -हेमकुंड साहिब (उत्तराखंड)
कामाख्या मंदिर (असम),
तवांग मठ-पीटीत्सो झील (अरुणाचल प्रदेश)
काठगोदाम-हनुमानगढ़ी मंदिर (उत्तराखंड)
रामटेक गाड मंदिर (महाराष्ट्र)
ब्रह्मगिरि-अंजनेरी (महाराष्ट्र)।

पर्वतमाला परियोजना भारत के बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण छलांग है, जो चुनौतीपूर्ण इलाकों में सतत और कुशल परिवहन को सक्षम बनाती है। वर्तमान और आगामी परियोजनाओं के साथ रोपवे भारत के परिवहन नेटवर्क का एक प्रमुख घटक बनने जा रहा है, जिससे यात्रा का समय कम होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरणीय स्थिरता को प्राथमिकता देते हुए आर्थिक विकास में तेजी आएगी। इस पहल का उद्देश्य सुरक्षित, लागत प्रभावी, सुविधाजनक और विश्व स्तरीय रोपवे अवसंरचना स्थापित करना है। इससे देश में लॉजिस्टिक कार्यकुशलता बढ़ाने और समग्र गतिशीलता में सुधार के लिए निर्बाध रूप से शुरू से लेकर दूरदराज एरिया में संपर्क सुनिश्चित हो सकेगा।

यह है 58514 करोड़ रुपये के प्रस्तावित बजट का आकार

- पहली बार ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ध्यान केन्द्रित
- प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 6.7 % की वृद्धि अनुमानित
- प्रतिव्यक्ति आय 2,57,212 रुपये अनुमानित
- राज्य का जी.डी.पी. 2,32,185 करोड़ रुपये अनुमानित

1. ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास हेतु कृषि, बागवानी, पशुपालन व सम्बद्ध क्षेत्रों का विकास एवं विस्तार।

जिला सोलन के दाड़लाघाट में कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान को क्रियाशील करना।

✓ Wool Federation के माध्यम से ऊन के सही रख-रखाव हेतु 450 वर्ग मीटर आकार के स्टोर का निर्माण।

✓ घुमन्तू भेड़ बकरी पालकों के Migratory Routes को Map करके GPS से Track किया जाएगा।

✓ दूध Procurement का कार्य कर रही पंजीकृत Societies को मिलने वाली Freight Subsidy को 1.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 3 रुपये प्रति लीटर किया जाएगा।

✓ Milkfed में दूध Procurement के कार्य को पूर्णतः डिजिटल किया जाएगा। साथ ही सभी पशुओं को भी Life Cycle Approach के अन्तर्गत एक Integrated Digital Platform पर लाया जाएगा।

Dairy Development योजना के तहत Milk Processing Plant डगवार, कांगड़ा में नई केंद्रीय परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना।

✓ नाहन, नालागढ़, मौहल, रोहड़ू में 20 हज़ार एलपीडी क्षमता के 4 नए संयन्त्र और ऊना और हमीरपुर में 2 Milk Chilling Centre(MCC) की स्थापना करना।

✓ गाय के दूध की खरीद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य को 45 से बढ़ाकर 51 तथा भैंस के दूध को 55 से बढ़ाकर 61 रुपये प्रति लीटर करना।

✓ किसी किसान या Society द्वारा 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित Notified Collection Centre पर दूध स्वयं ले जाने पर उन्हें 2 रुपये प्रति लीटर की दर से Transport Subsidy देना।

✓ प्रदेश के किसानों के हित में सरकार "Agriculture Loan Interest Subvention Scheme" लाएगी।

✓ एक लाख नए किसानों को प्राकृतिक खेती के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य।

✓ किसानों को "Certified Evaluation Tool For Agriculture Resource Analysis" (CETARA Portal) पोर्टल पर Register किया जाएगा।

✓ प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाये गये मक्का के लिए 40 रुपये और गेहूं 60 रुपये प्रति किलो ग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा जाएगा। यदि कोई किसान 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित Notified Collection Centre पर स्वयं ले कर आते हैं तो उन्हें 2 रुपए प्रति किलो की दर से Freight Subsidy दी जाएगी।

✓ किसानों को बेहतर Marketing के माध्यम से बेहतर मूल्य हेतु e-Commerce Platforms, NCDC से जोड़ना।

✓ जिला हमीरपुर में स्पाईस पार्क (Spice Park) का निर्माण।

✓ प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाई गई हल्दी के लिए 90 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा।

✓ कृषि विभाग के सभी Government Farms (सरकारी खेतों) को प्राकृतिक खेती के अन्तर्गत लाया जाएगा। पांच नए मॉडल फार्म विकसित किए जाएंगे।

✓ ऊना जिले में Potato Processing Plant को स्थापित करना।

✓ खरीफ़ 2025 से आठ Potato Development Stations में आलू के बीज का उत्पादन की शुरूआत।

✓ राज्य में अनाज Silos की स्थापना।

✓ हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण संवर्धन परियोजना के अन्तर्गत 100 गांवों में सिचाई योजनाओं का निर्माण करके उन्हें Local Committees को Transfer, कृषि बाड़बंदी व कृषि यन्त्रीकरण में सहायता प्रदान, किसानों के लिए लगभग 1 हज़ार 500 प्रशिक्षण शिविर, 4 हज़ार Demonstrations on Vegetable Cultivation व Millets पर लगभग 2 हज़ार 400 Demonstrations आयोजित करना।

✓ मुख्यमन्त्री खेत संरक्षण योजना' को आगे बढ़ाते हुए अब Solar Fencing, जाली धार और कान्टेदार बाड़बंदी में सहायता प्रदान।

✓ 4 हज़ार हैक्टेयर में 257 क्लस्टरों के लिए Topographic Survey किया जाएगा।

✓ किसान उद्यम नवाचार केन्द्र स्थापित किया जाएगा।

✓ प्रगति पर 114 Lift Irrigation Schemes वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूरी की जाएगी।

✓ HPSHIVA परियोजना के तहत 100 करोड़ रूपये का व्यय किया जाएगा।

✓ Weather based Crop Insurance Scheme केअन्तर्गत अब तीन और फल फसलों लीची, अनार तथा अमरूद को भी शामिल करना।

✓ Sub tropical बागवानी को बढ़ावा देने के लिए Sub tropical फलों के High Density Plantation के अन्तर्गत लाया जाएगा।

✓ जलाशयों से मछली प्राप्त कर रहे मछुआरों और मत्स्य कृषकों की Royalty की दर को घटाकर 7.5 प्रतिशत करना।

✓ मुख्यमन्त्री मत्स्य पालन योजना के तहत निजी क्षेत्र में 80 प्रतिशत सब्सिडी के साथ 20 हैक्टेयर नए मछली के तालाबों का निर्माण।

✓ 120 नई टांऊट इकाइयों का निर्माण।

✓ पतलीकूहल में एक टांऊट फिश ब्रूड बैंक की स्थापना।

✓ मछुआरों को पुरानी नाव बदलकर नई नाव खरीदने के लिए पात्रता के अनुरूप 40 से 60 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा।

✓ मछुआरों को Fish Transportation हेतु तिपहिया वाहन व मोटर साईकल का वितरण।

✓ 10 बायोफ्लॉक कल्चर इकाईयां, 03 टांऊट हेचरी, 04 मछली फीड मिल, 02 आईस प्लांट, 05 बायोफ्लॉक मछली तालाब और 02 सजावटी मछली पालन इकाईयों का निर्माण किया जाएगा।

2. पर्यटन से विकास की ओर अग्रसर हिमाचल।

✓ गगल स्थित हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए भू-अधिग्रहण का कार्य निर्धारित समय अवधि में पूरा कर लिया जाएगा।

✓ New Tourism Destinations के अन्तर्गत मनाली, कुल्लू, नग्गर व नादौन में वैलनेस सेन्टर, धर्मशाला, शिमला व मण्डी में आईस स्केटिंग रिंक, पालमपुर और नगरोटा बगवां का सौन्दर्यीकरण, बाबा बालकनाथ मन्दिर के परिसर में पर्यटन सुविधाएं व नादौन में रॉफ्टिंग सेन्टर।

✓ पर्यटकों की सुविधा एवं युवाओं को रोज़गार हेतु Food Vans की खरीद के लिए उपदान देना।

✓ Home Stay Units के लिए एक नई योजना 'मुख्यमन्त्री पर्यटन स्टार्ट-अप योजना' शुरू करने की जाएगी।

✓ एक नई योजना के तहत 200, 3 Star या उससे उपर 7 Star तक के होटल स्थापित करने के लिये निजि क्षेत्र को निवेश के लिए आमन्त्रित करेंगे।

✓ माता श्री चिन्तपूर्णी मन्दिर, माता श्री ज्वालाजी मन्दिर, श्री माता श्री नैना देवी मन्दिर के सौन्दर्यीकरण तथा धर्मशाला के तपोवन में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के Convention Centre का निर्माण।

✓ मण्डी में शिवधाम की परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करना।

✓ कांगड़ा जिले में पौंग डैम के साथ-साथ निकटतम क्षेत्रों के विकास हेतु नगरोटा सूरियां, खब्बल व Wellness Centre देहरा, काज़ा और रकछम व छितकुल को पर्यटन गंतव्यों के रूप में विकसित करना।

✓ बनखण्डी, कांगड़ा में Zoological Park में "Planetarium" स्थापित किया जाएगा।

✓ स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लक्ष्य से प्रदेश में चार नए Five Star स्तर के "Natural Care Wellness Centre" खोलना।

✓ सरकार द्वारा रक्कड़, पालमपुर, सुल्तानपुर, जसकोट और शारबो(किन्नौर) में हैलीपोर्टस का निर्माण और संचालन करना।

✓ सिक्किम, असम और पश्चिमी बंगाल की तर्ज़ पर प्रदेश के चाय बागानों को पर्यटन से जोड़ना।

✓ नई हिमाचल प्रदेश Eco-Tourism नीति-2024 के अनुसार प्रदेश में Eco-Tourism गतिविधियों को गति देना।

✓ वन विभाग के विभिन्न सर्कल में भी Eco-Tourism Societies गठित की गई हैं।

✓ Eco-Tourism की दिशा में 78 Eco-Tourism साईटों के आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।

✓ विभिन्न Eco-Tourism गतिविधियों के माध्यम से आगामी 5 वर्षों में लगभग 200 करोड़ रूपये अर्जित करने का लक्ष्य।

✓ पायलट आधार पर पपरोला और शिमला के आयुष अस्पतालों में पर्यटकों और आम जनता के लिए वैलनेस पंचकर्मा शुरू किया जाएगा।

✓ विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में पुलिस स्टेशनों/डैस्क को स्थापित करके इन्हे सम्बन्धित थानों के साथ एकीकृत किया जाना।

✓ कुल्लू के नग्गर में अन्तर्राष्ट्रीय रौरिक मेमोरियल ट्रस्ट के क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा।

3. समाज के सभी वर्गों का उत्थान एवं कल्याण।

✓ 2025-2026 के दौरान सामाजिक पैन्शन योजनाओं में 37 हज़ार नए लाभार्थियों को शामिल करना।

✓ सरकारी कर्मचारी/पैन्शनभोगियों और आयकर दाता दिव्यांगजनों को छोड़कर सभी विशेष योग्यजन व्यक्तियों (दिव्यांगजन) जिनकी बैंचमार्क विकलांगता 40 प्रतिशत या अधिक है उनको सामाजिक सुरक्षा पैन्शन योजना (SSP) देना।

✓ सामाजिक सुरक्षा पैन्शन (SSP) के वितरण में पारदर्शिता और इसे प्रभावी बनाने के लिए एक End-to-End एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल/प्लेटफार्म लान्च करना।

✓ इन्दिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाली हर बेटी को शामिल करना। महिलाएं जो Domestic Helper के रूप में कार्य कर रही हैं, उन्हें भी इस योजना से 1 जून 2025 से लाभान्वित किया जाएगा।

✓ Institution वित Children with Special Abilities (ICSA) ढली को कर्मचारियों सहित सरकार के अधीन करना।

✓ सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती आश्रय योजना (SJAY) के तहत, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बेघर पात्र व्यक्तियों को गृह निर्माण के लिए अन्य योजनाओं से समन्वय करते हुए अतिरिक्त संसाधान उपलब्ध करवाना।

✓ अन्तर्जातीय विवाह के लिए मिलने वाले मौद्रिक पुरस्कार को 50 हज़ार से बढ़ाकर 2 लाख रूपये करना।

✓ विकलांग व्यक्तियों के विवाह के लिए प्रोत्साहन नामक उप योजना के तहत 70 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले दिव्यांगजनों के विवाह हेतु विवाह प्रोत्साहन राशि 50 हज़ार से बढ़ाकर 2 लाख करना।

✓ मुख्यमन्त्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के तहत नए लाभार्थियों को शामिल करना।

✓ वृद्धजनों के लिए एकीकृत योजना के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर निजी क्षेत्र की भागीदारी से वृद्ध आश्रम/वरिष्ठ नागरिक गृह स्थापित करना।

✓ हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम के माध्यम से स्वरोज़गार और विभिन्न लघु उद्यमों आदि के लिए कम ब्याज दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए परिवार की निर्धारित वार्षिक आय को बढ़ाकर 50 हज़ार रूपये करना।

✓ राज्य में 3 और नशा रोकथाम एवं नशामुक्ति-सह-पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए जाने प्रस्तावित।

✓ बीपीएल परिवार में जन्म लेने वाली दो बालिकाओं के लिए ''इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना''।

✓ काम-काजी महिलाओं की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य सोलन, नीरी, दरुही, पालमपुर, लुथान, बद्दी, गगरेट, नगरोटा बगवां, चनौर इंडस्टियल एरिया और मेडिकल डिवाइस पार्क सोलन में कुल 13 Working Womens' Hostels का निर्माण कार्य आरम्भ किया जाएगा।

✓ 1 अप्रैल 2025 से सभी 18,925 आंगनवाड़ी केंद्रों को ''आंगनवाड़ी सह प्रीस्कूल'' के रूप में नामित कर इन्हें नजदीकी स्कूलों में यथासंभव Co-locate करना।

✓ छोटे बच्चों के स्वास्थ्य हेतु एक नई योजना ''इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना'' को लागू करना। नीति आयोग के साथ मिलकर जिला ऊना में पायलट आधार पर चलाए जाने वाले विंगस प्रोजेक्ट (World-leading Innovative Study Programme) को पूरा करना।

4 स्वरोजगार के क्षेत्र में नए कदम

✓ प्रदेश के शहरी क्षेत्र के छोटे फल-सब्जी विक्रेताओं, चाय दुकानदारों और अन्य के लिए मुख्यमन्त्री लघु दुकानदार कल्याण योजना लाने जा रही है।

✓ राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के तहत पात्र आवेदकों को ई-टैक्सी खरीदने हेतु सब्सिडी प्रदान करना जारी रखा जाएगा।

✓ तीन हज़ार डीजल/पैटोल Taxi वाहनों को इलैक्ट्रिक Taxi वाहनों (e-Taxi) में परिवर्तित करने पर e-Vehicles के लिए 40 प्रतिशत तक की Subsidy प्रदान की जाएगी।

✓ एक हज़ार बस रूटों के नए परमिट निजी क्षेत्र को आवंटित किए जाएंगे। इन रूटों पर बस अथवा टैम्पों टैंवलर की खरीद पर Subsidy/VGF प्रदान की जाएगी।

✓ नए स्थानों पर हिम-ईरा शॉप्स, हिमाचली हाट तथा साथ ही Wayside Amenities का निर्माण आरम्भ किया जाएगा। Wayside Amenities Scheme के प्रथम चरण में योजना राज्य राजमार्गो, राष्ट्रीय राजमार्गो और एक्सप्रेसवे के किनारे लागू की जाएगी।

✓ स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोबाइल फूड वैन दी जाएंगी।

✓ National Rural Livelihoods Mission (NRLM) के अन्तर्गत 4 हज़ार योग्य अभ्यार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके इन में से 70 प्रतिशत को सुनिश्चित रोज़गार उपलब्ध करवाया जाएगा।

✓ Bantony Castle शिमला के परिसर में दिल्ली हाट की तर्ज़ पर हि. प्र. राज्य ग्रामीण आजिविका मिशन के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों/शिल्पकारों हेतु स्टॉल स्थापित किए। राज्य की संस्कृति, भोजन और हस्तशिल्प को प्रदर्शित करने हेतु दिल्ली हाट में 'हिम उत्सव' का आयोजन किया जाएगा।

✓ जनजातीय क्षेत्रों तथा बड़ा भंगाल, डोडरा क्वार, कुपवी, तीसा और अन्य चिन्हित स्थानों पर निजी क्षेत्र में 250 किलोवॉट से एक मेगावाट तक की सौर परियोजना स्थापित करने के लिए 3-5 प्रतिशत का ब्याज उपदान प्रदान करेगी।

5. हरित ऊर्जा, हरित हस्तक्षेप, हरित हिमाचल, व स्वच्छ हिमाचल

✓ कांगड़ा के डमटाल में 200 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगाया जाना।

✓ ग्रीन पंचायत योजना के तहत 100 पंचायतों में 500-500 किलोवॉट के सोलर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे।

✓ शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना(450 मेगावाट) को दिसम्बर, 2026 तक चालू करने का लक्ष्य है। एकीकृत काशांग जल विद्युत परियोजना के कार्य को जून, 2026 तक पूर्ण

शेष पृष्ठ 6 पर........

यह है 58514 करोड़ रुपये के प्रस्तावित बजट

.....पृष्ठ 5 का शेष

करने का लक्ष्य।

✓ पम्प भण्डारण परियोजनाओं से बिजली क्षेत्र के विकास की गति में वृद्धि।

✓ निजी निवेश को उर्जा क्षेत्र में बढ़ाने हेतु प्रदेश सरकार की ओर से केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के उपक्रमों को निवेश का आमन्त्रण।

✓ कांगू (जिला मण्डी) और टहलीवाल (जिला ऊना) में 220 केवी सब-स्टेशन के कार्य की शुरूआत।

✓ धर्मपुर (जिला मण्डी) और बरसैनी (जिला कुल्लू) में 132 केवी के दो सब-स्टेशन की स्थापना की जाएगी।

✓ गनोग(नूरपुर), करला कोटला (देहरा), मझीण(ज्वालामुखी), मोकी (इन्दौरा), समलोटी(नगरोटा बगवां) और थेर(ज्वालामुखी) में आगामी वित्त वर्ष के दौरान 33KVA/11KVA के 6Sub Station की स्थापना की जाएगी।

✓ 80 पेटोल पम्पों पर ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन चालू करने के साथ-साथ ग्रीन कॉरिडोर पर 41 स्थानों पर PPP मोड पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना।

✓ 500 और e-Buses खरीदी जाएंगी।

✓ 100 जलवायु-संवेदनशील गावों की पहचान कर Climate-Smart Agriculture, और Renewable Energy Microgrids के माध्यम से विकास करने हेतु Climate Resilient Villages (CRV) Programme की शुरूआत

✓ चम्बा जिले में चार सरकारी संस्थानों और शिमला जिले में दो सरकारी संस्थानों में Dome Theater स्थापना।

✓ प्लास्टिक उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए Plastic Neutral Himachal अभियान की शुरूआत।

✓ Biodiversity Conservation and Protection में युवाओं की भागीदारी के लिए एक Biodiversity Guardianship Programme की शुरूआत।

✓ जिला हमीरपुर के सभी सरकारी कार्यालयों में समस्त पारम्पारिक ईन्धन वाले वाहनों के स्थान पर ई.वाहनों से परिवर्तित करने की शुरूआत करेगी।

मनरेगा के तहत वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए एक Standard Operating Procedure (SoP) लागू किया जाएगा।

✓ वन क्षेत्र के विस्तारीकरण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए 5 हज़ार हैक्टेयर भूमि पर का वृक्षारोपण का लक्ष्य तय करना।

✓ वन प्रबंधन तथा वन क्षेत्र विस्तार में समुदायों की भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु 100 करोड़ व्यय के साथ नई राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, लागू करना।

✓ Corporate Social Responsibility (CSR) के अन्तर्गत एक नई Adoption योजना लाकर बंजर भूमि पर वृक्ष लगाना।

✓ World Bank, KFW और JICA की सहायता से वन क्षेत्र में चल रही तीन परियोजनाओं के तहत अगले वर्ष के दौरान लगभग 200 करोड़ रूपये व्यय किए जाने का प्रस्ताव।

✓ कृषि-वानिकी फसल अवशेषों को मूल्यवान कार्बन उत्पादों में परिवर्तित करके आजीविका और पर्यावरण संरक्षण के अवसर में बदलने का प्रस्ताव।

6. स्वास्थ्य सेवाओं का आधुनिकीकरण व शिक्षा का रूपान्तरण।

✓ 69 संस्थानों में डॉयलेसिस सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

✓ 11 संस्थानों घवांडल, चवाड़ी, भोरंज, नादौन, तयारा, जयसिंहपुर,पधार, धर्मपुर, जुन्गा, हरोली व अम्ब में ब्लड स्टोरेज यूनिट्स की स्थापना।

✓ हमीरपुर, बिलासपुर, चम्बा, कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी, शिमला, सिरमौर और ऊना जिलों में 17 Newborn Stabilization Units स्थापित करना।

✓ AIMSS, Chamiana, Shimla व टॉण्डा मैडिकल कॉलेज, कांगड़ा में Robotic Surgery की स्थापना।

✓ IGMC Shimla में Positron Emission Tomography (PET) बंद की सुविधा की उपलब्ध करवाना।

✓ IGMC Shimla, AIMSS Chamiana, Shimla, Govt. Medical College Hamirpur तथा Govt Medical College Ner Chowk में अत्याधुनिक MRIs मशीनें की स्थापना।

✓ राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर और राजकीय मेडिकल कॉलेज मण्डी में कैथेटराइजेशन लैब (Cath. Lab.) की स्थापना करना।

✓ निजी क्षेत्र के सहयोग से 10 नए Health and Wellness Centres की स्थापना करना।

✓ रोगी मित्र योजना के अन्तर्गत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में एक हज़ार के करीब रोगी मित्र नियुक्ति व इन्हें 15 हज़ार मासिक मानदेय प्रदान करना।

✓ सुगम स्वास्थ्य नाम की नई App को लॉन्च करना।

✓ मुफ्त इन्सुलिन पम्प उपलब्ध अब 27 वर्ष तक के लड़के और लड़कियों के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे।

✓ गम्भीर बीमारियों से ग्रसित लगभग 12 हज़ार रोगियों के लिए पैलिएटिव केयर सेवाएं उपलब्ध करवाना।

✓ मुख्यमन्त्री वृद्धजन देखभाल योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य और पैरामेडिकल स्टॉफ मोबाइल स्वास्थ्य वैन के माध्यम से 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोगों के घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाना।

✓ प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए 25 Advanced Life Support एम्बुलेंस की खरीद करना।

✓ जिला कांगड़ा में 50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू।

✓ आचार्य चरक योजना की शुरूआत की जाएगी, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी आयुष अस्पतालों और औषधालयों में मरीजों को निःशुल्क जांच और आवश्यक दवाइयां उपलब्ध करवाई जाएंगी।

✓ प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों और अध्यापकों की Digital Attendance शुरू की जाएगी।

✓ Government Senior Secondary Schools गगरेट, अम्ब, हरोली, बंगाणा, बड़सर, सुजानपुर, धर्मशाला, ज्वाली, इन्दौरा, सरकाघाट, हमीरपुर, भोरंज, बड़ा, नादौन, घुमारवीं, देहरा, जयसिंहपुर, शाहपुर, भटियात, फतेहपुर, पालमपुर, अर्की, सिराज, ढलियारा, शिलाई, रिकांगपिओ (किन्नौर), केलांग, ठियोग, नगरोटा, कुल्लू और जोगिन्द्रनगर को राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा।

✓ शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रबंधन के लिए शिक्षा निदेशालयों का पुनर्गठन किया जाएगा।

✓ सुजानपुर स्थित सैनिक स्कूल को Hostel की मुरम्मत के लिए 3 करोड़ रूपये की राशि प्रदान की जाएगी।

✓ कांगड़ा में कॉलेज की छात्राओं के लिए 4 Hostel बनाए जाएंगे। साथ ही हमीरपुर और सुजानपुर में स्कूली लड़कियों के लिए Hostel बनाए जाएंगें।

✓ तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अत्याधुनिक विचारों और पहलों को शुरु करने के लिए Innovation Fund की स्थापना।

✓ राजकीय हाईडो इन्जीनियरिंग महाविद्यालय बान्दला में एम.टैक इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (Electrical Vehicle Technology) की कक्षाएं चलाई जाएगी।

✓ जिला बिलासपुर के घुमारवीं में Digital University of Innovation, Entrepreneurship, Skill, and Vocational Studies की स्थापना सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP Mode) व Self Financing पर की जाएगी।

7. नशामुक्त हिमाचल।

✓ नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम हेतु Drug Dependence Prevention, De-addiction, and Rehabilitation Board का गठन करना।

✓ मैडिकल कॉलेज, टाण्डा में एक Drug-De-addiction and Rehabilitation नोडल केन्द्र स्थापित करना।

सिरमौर जिले में एक Drug-De-addiction and Rehabilitation केंद्र चालू किया जाएगा।

✓ क्षेत्रीय/जिला/मेडिकल कॉलेजों /अस्पतालों में आवश्यकता के अनुसार डि-एडिक्शन बैडस की संख्या में बढ़ोतरी करना।

✓ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) के डॉक्टर और पैरामैडिकल स्टॉफ द्वारा नजदीकी स्कूलों में छात्रों की स्वास्थ्य जांच व Counselling- cum-Awareness Session हेतु स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत।

✓ HP Anti Drug Act के प्रावधानों के माध्यम से नशे से जूझ रहे लोगों के लिए Punitive Measures के स्थान पर पुर्नवास पर जोर।

✓ नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए Special Task Force (STF) बनाने की घोषणा।

✓ संगठित अपराध सिण्डिकेट या गिरोह द्वारा गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम और नियन्त्रण के लिए "Himachal Pradesh Prevention of Continuing Unlawful Activity and Control of Organized Crime Act, 2025. लाया जाना।

8. स्वच्छ पेयजल एवं सीवरेज सुविधाओं के क्षेत्र में विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण।

✓ जिला लाहौल स्पिति के लिए 27 करोड़ रूपये की लागत से 20 Water Supply Schemes और किन्नौर जिले में 72 करोड़ रूपये की लागत से 6 Water Supply Schemes का कार्य आरम्भ किया जाएगा।

✓ नादौन, भोरन्ज, अमलेहड़ और हरोली में 4 Water Supply Schemes और बद्दी के लिए एक Sewerage Scheme का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा।

✓ भुन्तर, नाहन, ज्वाली, अर्की, निरमण्ड, जोगिन्द्रनगर, शाहपुर, भटियात और करसोग नगरों में कुल 167 करोड़ रूपये की लागत से पेयजल योजनाओं का निर्माण शुरू किया जाएगा।

✓ कुल 12 शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 24X7 पेयजल आपूर्ति प्रणाली के अन्तर्गत 5 क्षेत्रों में कार्य प्रगति पर है तथा शेष क्षेत्रों में शीघ्र ही कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

✓ हिमाचल प्रदेश ग्रामीण पेयजल उन्नयन परियोजना के तहत 7सौ 45 करोड़ की लागत से 8 जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में 20 हजार 663 घरों तक बेहतर आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

✓ हिमाचल प्रदेश ग्रामीण पेयजल उन्नयन एवं आजीविका परियोजना के तहत Functional House Hold Tap Connection(FHTCs) का शेष 57 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जाएगा।

✓ हिमाचल प्रदेश में जल आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से 200 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ नई मुख्यमंत्री स्वच्छ जल शोधन योजना की शुरूआत।

✓ जिला कांगड़ा के देहरा, ज्वाला जी, जंसवां व प्रागपुर में आगामी वित्त वर्ष के दौरान 43 करोड़ रूपये की लागत से Drinking Water Treatment Plant लगाया जाएगा।

✓ पीने के पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 14 Bacteriological मापदण्डों लिए जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी।

✓ नेरवा, चौपाल, राजगढ़, शाहपुर और बिलासपुर नगरों के लिए सीवरेज योजनाओं का कार्य 2025-2026 में आरम्भ कर दिया जाएगा।

✓ कांगड़ा, मण्डी, चम्बा और किन्नौर ज़िलों के 14 कस्बों में सीवरेज योजनाओं पर कार्य 2025-2026 में शुरू किया जाएगा।

9. परिवहन, उद्योग, पुल व सड़कें

✓ परिवहन निगम में अतिरिक्त 500 e-Buses की खरीद व ऑनलाईन पास सुविधा शिमला के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य स्थानों में शुरू करने हेतु Software तैयार किया जाएगा।

✓ शिमला शहर में 1 हज़ार 546 करोड़ 40 लाख रूपये की लागत से 14. 79 किलो मीटर लम्बी रोपवे का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

✓ शिमला शहर में पायलट आधार पर Luxury Vehicles को चयनित रूटों पर चलाए जाएगें।

✓ ऊना जिले के हरोली में पहला Automatic Driving Test Track स्थापित किया जाएगा।

✓ जलमार्गों में जैटीज़ आदि का विकास और क्रूज़ पर्यटन, जल क्रीड़ा गतिविधियों और जल परिवहन सेवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।

✓ बल्क डंग पार्क में आगामी वर्ष में कार्य को सुचारू रखने के लिए आवश्यकता अनुसार बजट का प्रावधान करना।

✓ प्रदेश की औद्योगिक नीति में मूलभूत बदलाव करना। हरित ऊर्जा, सौर ऊर्जा, दुग्ध उत्पादन व इलैक्ट्रिक व्हीकल जैसे क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने हेतु Investor Outreach Programmes आयोजित किए जाना।

✓ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को सुदृढ़ बनाने हेतु प्रयास।

✓ एक उच्च स्तरीय बोर्ड का गठन किया जाएगा, जो राज्य के औद्योगिक क्षेत्र से सम्बन्धित सभी पहलुओं पर विचार करेगा और सभी मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल करेगा।

✓ 66 KV या उससे अधिक सप्लाई वोल्टेज पर चलने वाले उद्योगों को राहत देने के लिए 40 पैसे प्रति यूनिट बिजली की खपत पर सब्सिडी दी जाएगी।

✓ 3 सौ 45 करोड़ 14 लाख रूपये की लागत से 6 सड़कों एवं पुलों की परियोजनाओं के निर्माण की शुरूआत।

✓ NABARD के तहत 4 सौ 98 करोड़ 62 लाख रूपये की 50 सड़कों एवं पुलों की परियोजनाओं की स्वीकृति।

✓ निविदाओं के प्रकाशन की अवधि 14 दिन से घटाकर 7 दिन करना तथा कार्यों को Award तक करने का कुल समय 12 दिन करके निष्पादन में तेजी लाना।

✓ मुख्यमन्त्री सड़क योजना के अन्तर्गत 100 करोड़ रूपये का प्रावधान करना।

10. ग्रामीण विकास, पचायती राज व शहरी विकास के क्षेत्र में कार्य

✓ प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं सुचारु बनाने के लिए हम ब्लॉकों का पुनर्गठन करेंगे।

✓ ग्रामीण संस्थानों को सशक्त बनाने के लिए 09 विस्तार प्रशिक्षण केंद्र (Extension Training Centres) स्थापित किए जाएंगे।

✓ पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को पानी की योजनाओं को पंचायत स्तर पर देगें ताकि वे अपनी आय में बढ़ौतरी कर सकें तथा आय के अतिरिक्त संसाधनों को बढ़ाने के उद्देश्य से उनकी सम्पतियां की Lease Management की जाएगी।

✓ 2025-2026 हेतु 15वें वित्त आयोग के तहत पंचायतों में विकास कार्य हेतु 452 करोड़ रूपये तथा राज्य वित्त आयोग के तहत 467 करोड़ रूपये व्यय किए जाएंगे।

✓ नगर निगम हमीरपुर, ऊना और बद्दी के लिए प्रत्येक को एक करोड़, नगर परिषद नादौन, बैजनाथ-पपरोला और सुन्नी के लिए 25 लाख प्रत्येक तथा नवगठित 14 नगर पंचायतों के 19 लिए 50 लाख प्रत्येक के रूप में विकासात्मक अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।

✓ नव गठित शहरी निकायों में शामिल किए गए ग्रामीण क्षेत्रों में 3 वर्षों तक पानी के रेट पहले के समान ही रहेंगें।

✓ शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से प्रदान की जा रही लगभग 44 सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से PYOG प्लेटफार्म पर लाया जाएगा।

✓ वर्तमान विकास योजनाओं का पुनर्निरीक्षण तथा महत्वपूर्ण शहरी/पर्यटक क्षेत्रों में "Business District Zone" की स्थापना।

11 राजस्व, आपदा व दमकल

✓ सभी राजस्व न्यायालयों को चरणबद्ध तरीके से डिजिटल करना तथा प्रदेश में ई-राजस्व प्रणाली लागू करना।

✓ Revenue Court Management System(RM) के अन्तर्गत एक मॉड्यूल विकसित करना जो नागरिकों से सम्बन्धित भूमि रिकॉर्ड के सीमांकन और नामान्तरण से जुड़े मामलों की मैपिंग।

✓ Aerial Survey Technology के माध्यम से चयनित शहरी क्षेत्रों में वास्तविक जमीनी स्थिति के अनुसार राजस्व रिकार्ड तैयार करना।

✓ डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से ततीमा(Maps) उपलब्ध करवाने हेतु भू-नक्शा एप्लीकेशन का उपयोग।

✓ ऑनलाइन म्यूटेशन सॉफ्टवेयर शुरू करके म्यूटेशन की प्रक्रिया को डिजिटल करना और एक पेपरलेस प्रणाली स्थापित करना।

✓ आपदाओं से निपटने के लिए 3 हजार 645 पंचायतों में एक संगठित और सामुदायिक संचालित पंचायत आपातकालीन प्रतिक्रिया केन्द्र की स्थापना।

✓ AFD के माध्यम से लगभग 892 करोड़ रूपये की लागत से आगामी

शेष पृष्ठ 7 पर.....

यह है 58514 करोड़ रुपये के

........पृष्ठ 6 का शेष

पांच वर्षों के लिए परियोजना के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं:-

✓ Disaster Risk Reduction and Preparedness Project के तहत Multi Hazards के लिए Early Warning System का विकास और GIS पर आधारित Decision Support System.

✓ राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के परिसरों की स्थापना।

✓ भूस्खलन रोकने और ढलानों को स्थिर करने के लिए BioEngineering उपायों का प्रोत्साहन।

✓ उप-मण्डल और तहसील स्तर पर भी "Disaster Risk Reduction Coordination Centre" की स्थापना। HP State Disaster Management Authority, District Disaster Management Authorities, State Emergency Operation Cell, District Emergency Operation Cells को सुदृढ़ करना।

✓ कृषि और बागवानी के लिए जलवायु/मौसम पूर्वानुमान का विकास।

✓ जंगल की आग के खतरों को कम करने के लिए गतिविधियों को बढ़ावा।

✓ जलवायु परिवर्तन और अनुकूलन से सम्बन्धित अध्ययन।

✓ भूकंप-प्रतिरोधी तकनीकों को बढ़ावा देना।

✓ Disaster Risk Reduction के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का विकास।

✓ Himalayan Disaster Risk Reduction Centre की पालमपुर स्थापना।

✓ राजगढ़ जिला सिरमौर और कण्डाघाट जिला सोलन में दमकल केंद्र खोलना।

✓ नादौन, इन्दौरा, राजगढ़, और कण्डाघाट में 8 नए अग्निशमन वाहनों को क्रय करना और पुराने 60 अग्निशमन वाहनों के स्थान पर चरणबद्ध तरीके से नए वाहनों को खरीदना।

✓ 16 क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल, प्रशिक्षण और जनसमुदाय को जागरूकता प्रदान करने हेतु 2 बसें और विभिन्न प्रकार के अग्निशमन उपकरणों को खरीदना।

✓ उप दमकल केन्द्र काज़ा व कुमारसैन, जोगिन्द्रनगर, फतेहपुर व आनी की दमकल चौकियों के विभागीय भवनों का निर्माण।

12. भर्तियां

✓ महाविद्यालयों/विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के कुल 1000 पद भरे जाएंगे।

✓ आयुष चिकित्सा अधिकारियों के 200, होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों के 3, सोवा रिग्पा चिकित्सा अधिकारियों के 3, यूनानी चिकित्सा अधिकारियों के 2, आयुर्वैदिक फार्मेसी अधिकारियों के 52, लैब तकनीशियनों के 32, स्टाफ नर्सों के 33, ए.एन.एम. के 82, जे.ओ.ए.(आई.टी.) के 42 पदों को भरा जाएगा।

✓ पुलिस विभाग में पुलिस कॉस्टेबलों 1 हज़ार रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया वित्त वर्ष 2025-2026 में आरम्भ कर दी जाएगी।

✓ पुलिस कांस्टेबल की पदोन्नति से सम्बन्धित बी0-1 परीक्षा लगभग 500 पदों हेतु करवाई जाएगी।

✓ गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में होमगार्ड स्वयं सेवक ड्राईवरों के 113 पदों को आगामी वित्त वर्ष में भरा जाएगा।

✓ पंचायत सचिवों के 853 पदों को सीधी भर्ती से व तकनीकी सहायकों के 219 पद भरे जाएगें।

✓ स्वास्थ्य सुविधाएं सुचारू रूप से उपलब्ध करवाने के लिए अतिरिक्त 290 आशा कार्यकर्ताओं का चयन किया जाएगा।

✓ सभी श्रेणियों की 25 हजार भर्तियां।

13. कर्मचारी कल्याण

✓ 15 मई से प्रथम चरण में 70 वर्ष से 75 वर्ष के आयु वर्ग के पेंशनरों के बकाया एरियर का भुगतान इस वित्तीय वर्ष में किया जाएगा। चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों व अधिकारियों को उनके बकाया वेतन एरियर का चरणबद्ध से भुगतान किया जाएगा।

✓ 15 मई से प्रदेश के कर्मचारियों को 3 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ते की किश्त।

✓ दिहाड़ीदारों को 25 रुपये बढ़ौतरी के साथ 425 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी।

✓ आउटसोर्स कर्मियों को अब न्यूनतम 12,750 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

✓ मनरेगा मजदूरी को 20 रुपये बढ़ाकर 320 रूपये किया जाएगा।

14 मानदेय

✓ अध्यक्ष, जिला परिषद को 25,000 रुपये, उपाध्यक्ष, जिला परिषद को 19,000 रुपये, सदस्य, जिला परिषद को 8,300 रुपये, अध्यक्ष, पंचायत समिति को 12,000 रुपये, उपाध्यक्ष, पंचायत समिति को 9,000 रुपये, सदस्य, पंचायत समिति को 7,500 रुपये, प्रधान, ग्राम पंचायत को 7,500 रुपये, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत को 5,100 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा तथा सदस्य, ग्राम पंचायत को 1050 रुपये प्रति ग्राम पंचायत बैठक हेतु मानदेय मिलेगा।

✓ महापौर, नगर निगम को 25,000 रुपये, उप-महापौर, नगर निगम को 19,000 रुपये, काउंसलर, नगर निगम को 9,400 रुपये, अध्यक्ष, नगर परिषद को 10,800 रुपये, उपाध्यक्ष, नगर परिषद को 8,900 रुपये, पार्षद, नगर परिषद को 4,500 रुपये, प्रधान, नगर पंचायत को 9,000 रुपये, उप-प्रधान, नगर पंचायत को 7,000 रुपये तथा सदस्य, नगर पंचायत को 4,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

✓ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 10,500 रुपये, मिनी आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 7,300 रुपये, आंगनवाड़ी सहायिका को 5,800 रुपये, आशा वर्कर को 5,800 रुपये, मिड डे मील वर्कर्ज़ को 5,000 रुपये, वाटर कैरियर (शिक्षा विभाग) को 5,500 रुपये, जल रक्षक को 5,600 रुपये, जल शक्ति विभाग के Multi Purpose Workers को 5,500 रुपये, पैरा फिटर तथा पम्प-ऑपरेटर को 6,600 रुपये, पंचायत चौकीदार को 8,500 रुपये, राजस्व चौकीदार को 6,300 रुपये, राजस्व लम्बरदार को 4,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

✓ सिलाई शिक्षकों के मासिक मानदेय में 500 रूपये, लोक निर्माण विभाग के Multi Task Workers के मासिक मानदेय को 500 रुपये प्रतिमाह, SMC अध्यापकों के मासिक मानदेय में 500 रुपये प्रतिमाह, IT Teachers को 500 रुपये प्रतिमाह, SPOs को 300 रुपये प्रतिमाह बढ़ौतरी की जाएगी।

✓ प्रदेश के Medical Colleges/ AIMSS Chamiana में PG विद्यार्थियों के लिए Senior Resident/Tutor Specialist को वर्तमान में वज़ीफे की राशि को बढ़ाकर एक लाख रूपये की जाएगी तथा साथ ही DNB- Super Specialist - Sr. Residents-Super Specialist(D.M./M.Ch.) के वज़ीफे की राशि को भी बढ़ाकर एक लाख 30 हजार रूपये की जाएगी।

✓ प्रदेश में ऑउटसोर्स पर नियुक्त Operation Theater Assistant and Radiographer, की मासिक मानदेय राशि बढ़ाकर 25 हज़ार रूपये की जाएगी।

15 अन्य

✓ आम नागरिकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल को और प्रभावी बनाने के लिए इसमें Artificial Inteligence (AI) का प्रयोग किया जाएगा।

✓ शिमला के मैहली और कांगडा के चैतडू में स्थापित किए जा रहे Software Technology Park(STPI) पर कार्य पूरा किया जाएगा।

✓ सरकार Drone Taxi सेवाएं उपलब्ध करवाने की योजना बनाएगी। Drone Technology Intervention से कृषि एवं बागवानी के क्षेत्रें में भी आधुनिकीकरण के दृष्टिगत जिला हमीरपुर, मण्डी और कांगड़ा में Drone Station स्थापित किए जाएगें।

✓ बसाल (बिलासपुर) और बिन्द्रावन (पालमपुर) में आवासीय कलौनियां तथा रामपुर फेज-3, रजवाड़ी (मण्डी) व धर्मपुर (सोलन) में लगभग 82 फ्लैटों और 137 रिहायशी प्लाटों को विकसित किया जाएगा।

✓ हिमुडा द्वारा विकासनगर, शिमला में 250 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से एक विशाल व्यवसायिक परिसर के निर्माण किया जाएगा।

✓ बिलासपुर के लूहणू में 100 बिस्तरों वाला खेल छात्रावास। जिला हमीरपुर के खरीड़ी में 50 बिस्तरों वाले खेल छात्रावास।

✓ शिमला जिला के कुटासनी में राजीव गांधी बहुद्देशीय स्टेडियम में अत्याधुनिक खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण।

✓ सोलन में इण्डोर स्टेडियम के साथ-साथ रिंकांगपिओ, हरोली और जयसिंहपुर में स्टेडियम का निर्माण।

✓ हमीरपुर तथा सुजानपुर में Synthetic Track and Field सुविधा का निर्माण।

✓ विभागों में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित 15 प्रतिशत् पदों को प्राथमिकता से भर्ती।

✓ Sainik School में पढ़ रहे बच्चों को दी जाने वाली Diet Money को 10 रूपये से बढ़ाकर 50 रूपये करने की घोषणा।

✓ हम Climate Change को देखते हुए जनजातीय क्षेत्रों के लिए एक दूरगामी नीति बनाई जाएगी।

✓ सरकार द्वारा राज्य के छोटे मन्दिरों को वर्तमान में दी जा रही अनुदान की राशि को दोगुना करना।

✓ विधायक अपनी प्राथमिकताओं में अपने विधानसभा चुनाव क्षेत्र से डे-बोर्डिंग स्कूलों को भी सम्मिलित कर पाएंगे।

✓ विधायक प्राथमिकता योजनाओं के प्रति विधानसभा चुनाव क्षेत्र की वर्तमान सीमा 195 करोड़ रुपये को बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये करने की घोषणा।

प्रधान मंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिये प्रदेश से 5961 आवेदन

शिमला/शैल। केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा राज्य मन्त्री श्रीपद नायक ने राज्य सभा सांसद इंदु बाला गोस्वामी को संसद में बताया की प्रधान मंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अन्तर्गत 02/03/2025 तक हिमाचल प्रदेश से 5961 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमे से सर्वाधिक 1,659 आवेदन कांगड़ा जिला जबकि सबसे कम 21 आवेदन लाहौल स्पीति से प्राप्त हुए हैं।

उन्होंने बताया की प्रधान मंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अन्तर्गत बिलासपुर से 539, चम्बा से 226, हमीरपुर से 824, किन्नौर से 41, कुल्लू से 193, मंडी से 743, शिमला से 397, सिरमौर से 357, सोलन से 422, और ऊना से 539 आवेदन पत्र प्राप्त हुए है।

उन्होंने बताया की हिमाचल सहित विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए आवासीय क्षेत्रों में पहले दो किलो वाट क्षमता के रूफ टॉप सोलर स्थापित करने के लिए 33,000 रूपये प्रति प्रति किलो वाट की केन्द्रीय वितीय सहायता प्रदान की जा रही है जबकि एक किलो वाट क्षमता के रूफ टॉप सोलर स्थापित करने के लिए 19,800 रुपये की केन्द्रीय वितीय सहायता प्रदान की जा रही है जबकि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के मामलों में 19,800 रूपये प्रति किलो वाट की केन्द्रीय वितीय सहायता प्रदान की जा रही है।

पी एम श्री योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में 180 स्कूलों का चयन

शिमला/शैल। पी एम श्री योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में 180 स्कूलों का चयन किया गया है।

केन्द्रीय शिक्षा राज्य मन्त्री जयंत चौधरी ने संसद में लोक सभा सदस्य डॉ. राजीव भारद्वाज को बताया की पीएम श्री योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में 56 प्राथमिक, 5 सैकण्डरी स्कूल, और 119 सीनियर सैकण्डरी स्कूलों का चयन किया गया है ।

उन्होंने बताया की पीएम श्री योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और केन्द्र शासित राज्यों द्वारा संचालित 14500 स्कूलों की ढांचागत सुविधाओं को सुदृढ़ करने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया की इन स्कूलों को नेशनल एजुकेशन पालिसी 2020 के अन्तर्गत मॉडल स्कूल स्थापित करने का प्रावधान किया गया है जोकि बच्चों को खुशनुमा माहौल में उच्च क्वालिटी शिक्षा प्रदान करेंगे।

जयंत चौधरी ने संसद में लोक सभा सदस्य डॉ. राजीव भारद्वाज को बताया की पीएम श्री योजना के अन्तर्गत कुल 27,360 करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे जिसमे से केन्द्र सरकार 18,128 करोड़ और राज्य सरकारें 9,232 करोड़ रूपये की हिस्सेदारी की अदायगी करेंगी।

उन्होंने बताया की योजना के अन्तर्गत स्मार्ट क्लास रूम, डिजिटल लाइब्रेरी और आई सी टी सुविधाओं का प्रावधान किया गया है तथा बच्चों को पाठयक्रम चयन करती बार बेहतर विकल्प प्रदान किये गए हैं। उन्होंने बताया की योजना के अन्तर्गत शिक्षा को मातृ भाषा में प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि छात्रों और शिक्षकों में बीच भाषा के अवरोधों को खत्म किया जा सके।

हिमाचल में वर्ष 2023-24 में 22 पुलों की 254 सड़क परियोजनायें स्वीकृति

शिमला/शैल। केन्द्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मन्त्री नितिन गडकरी ने लोक सभा सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज को संसद में बताया की प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023-24 के दौरान 2,683 किलोमीटर लम्बी सड़कों और 22 पुलों की 254 सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई।

उन्होंने बताया की इस अवधि के दौरान प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में 185 किलोमीटर लम्बी सड़कों की 19 सड़क परियोजनाएं, चम्बा जिला में 167 किलोमीटर लम्बी सड़कों और 1 पुल की 17 सड़क परियोजनाएं, हमीरपुर जिला में 178 किलोमीटर लम्बी सड़कों की 21 सड़क परियोजनाएं, कांगड़ा जिला में 502 किलोमीटर लम्बी सड़कों और 5 पुलों की 55 सड़क परियोजनाएं, कुल्लू जिला में 103 किलोमीटर लम्बी सड़कों और 1 पुल की 10 सड़क परियोजनाएं, लाहौल स्पीति जिला में 64 किलोमीटर लम्बी सड़कों की 7 सड़क परियोजनाएं, मण्डी जिला में 322 किलोमीटर लम्बी सड़कों की 23 सड़क परियोजनाएं, शिमला जिला में 549 किलोमीटर लम्बी सड़कों की 46 सड़क परियोजनाएं, सिरमौर जिला में 163 किलोमीटर लम्बी सड़कों की 12 सड़क परियोजनाएं, सोलन जिला में 291 किलोमीटर लम्बी सड़कों और 4 पुलों की 25 सड़क परियोजनाएं और ऊना जिला में 159 किलोमीटर लम्बी सड़कों और 11 पुलों की 19 सड़क परियोजनाएं, स्वीकृत की गई।

भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत फरवरी 2025 तक 4,92,562 करोड़ रुपये खर्च

शिमला/शैल। केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राज मार्ग मन्त्री नितिन गडकरी ने राज्य सभा सांसद सुश्री इंदु बाला गोस्वामी को संसद में बताया की भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत 28 फरवरी 2025 तक कुल 4,92,562 करोड़ रूपये खर्च किये गए हैं। उन्होंने बताया की देश में 34800 किलो मीटर सड़क मार्ग निर्माण के लिए सरकार ने वर्ष 2017 में भारत माला परियोजना की शुरुआत की थी।

उन्होंने बताया की भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत 28 फरवरी 2025 तक कुल 26,425 किलो मीटर निर्माण कार्य का कार्यअवार्ड किया गया है जिसमे से ग्रीन फील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर सहित 19,826 किलो मीटर सड़क निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया की भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत 16 नवम्बर 2023 आगामी स्वीकृतियों पर रोक लगा दी गई है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिटंर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

बजट अनुमानों में 30% का अन्तर आना शुभ संकेत नहीं अनुपूरक मांगों से उठे सवाल

- 17000 करोड़ से अधिक की अनुपूरक मांगों को कैसे पूरा किया गया?
- बढ़ा हुआ खर्च पूरा करने के लिये जनता पर कितना बोझ डाला गया और कितना कर्ज लिया गया?

शिमला/शैल। सुक्खू सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए 17053.78 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया है। इस वित्तीय वर्ष के लिये सरकार ने 58444 करोड़ के अनुमान का बजट पेश किया था। इस बजट में 46667 करोड़ का राजस्व व्यय और 42153 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां दिखायी गयी थी। बजट अनुमानों के अनुसार यह वर्ष 10784 करोड़ के घाटे पर बन्द होना था। लेकिन अनुपूरक बजट ने सरकार की वित्तीय स्थिति पर कुछ गंभीर सवाल खड़े कर दिये हैं। अनुपूरक बजट में यह विवरण दिया गया है कि बढ़ा हुआ खर्च किन मुद्दों पर खर्च हुआ है। सत्रह हजार करोड़ से अधिक के अनुपूरक बजट से यह सामने आया है कि सरकार के मूल अनुमानों में करीब 30% की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि क्यों हुई है और इसका आने वाले समय सरकार की राजस्व आय पर भी कोई असर पड़ेगा या यह बढ़ौतरी नियमित राजस्व व्यय का ही हिस्सा बनकर रह जायेगी। क्योंकि सामान्यत: हर वर्ष खर्चो में दस प्रतिशत की मानक वृद्धि लेकर अगले बजट अनुमान तैयार किये जाते हैं। ऐसे में वर्ष 2025-26 का बजट अनुमान 80,000 करोड़ लगभग रहने का अनुमान है। वर्ष 2024-25 के 58444 करोड़ के बजट अनुमानों में वर्ष 10784 करोड़ के घाटे पर बन्द हो रहा था। अब जब अनुपूरक मांगों को मिलाकर बजट का कुल आकार ही 75000 करोड़ पहुंच जाता है तब आगे का यह बजट निश्चित रूप से 80000 तक पहुंचेगा ही।

वर्ष 2024-25 में राजस्व आय 42153 करोड़ की अनुमानित थी। तब इस वर्ष 10% की वृद्धि के साथ क्या यह 65000 करोड़ हो पायेगी यह देखना बड़ा सवाल होगा। क्योंकि इसी वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा वित्तीय संसाधन बढ़ाने के लिये किये गये उपायों से राजस्व आय में कितनी वृद्धि हुई है इसका आंकड़ा तो अगले बजट के अनुमानों में ही सामने आयेगा। लेकिन अनुपूरक बजट से जो खर्च बढ़ा है उसका आंकड़ा तो सामने आ गया है। परन्तु इस खर्च को पूरा करने के लिये कितने टैक्स लगाये जायेंगे और कितना कर्ज लिया जायेगा तो आगे ही सामने आयेगा। क्योंकि आगे चलकर सरकार को गारंटीयां भी पूरी करनी है। अभी तो राज्यपाल के अभिभाषण में यह गारंटीयां लागू हो गयी हैं। परन्तु आगे चलकर इनको व्यवहारिक रूप में भी पूरा करना होगा। चालू वित्त वर्ष में 17000 करोड़ से अधिक का खर्च बढ़ने पर इसको पूरा करने के लिये कितना कर्ज लिया गया है और भविष्य में और कितना कर्ज लिया जायेगा यह अभी सामने आना बाकी है। विपक्ष के मुताबिक सरकार 30000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। लेकिन अनुपूरक बजट में जब खर्च ही करीब 17000 करोड़ बढ़ा है तो इससे अधिक कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये।

ऐसे में अब यह विपक्ष की जिम्मेदारी हो जाती है कि वह इस बढ़े हुये खर्च का विवरण लेकर उस प्रदेश की जनता के सामने रखे। इसमें यह भी सामने आना चाहिये कि सही में कौन सी तत्कालिक आवश्यकताओं पर यह खर्च किया गया। इस खर्च को पूरा करने के लिये जनता पर कितना बोझ डाला गया और कितना कर्ज लिया गया। क्योंकि किसी सरकार के बजट अनुमानों में 30% तक का अन्तर आना कोई शुभ संकेत नहीं है। इतना बड़ा अंतर किसी प्राकृतिक आपदा के बिना जायज नहीं ठहराया जा सकता। क्योंकि अनुपूरक बजट वर्ष के अन्त में विभिन्न मांगों में हुए खर्च के सर प्लस या सरन्डर से प्रभावित नहीं होता है। बजट आवंटनों की समीक्षा वित्त विभाग वर्ष में तीन चार बार करता है। इसलिये यह अब माननीय के विवेक और ईमानदारी पर सीधा सवाल आ जाता है कि बजट अनुमानों में आये इस अन्तर का पूरा ब्योरा कारणों सहित प्रदेश की जनता के सामने रखे।

देहरा विधानसभा उपचुनाव में कांगड़ा बैंक द्वारा महिला मण्डलों को आर्थिक सहायता देना आया सवालों में

- क्या यह आचरण आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है?
- यह प्रकरण भाजपा पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह है

शिमला/शैल। ई.डी. सूत्रों से यह बाहर आया था की देहरा विधानसभा उपचुनाव के दौरान क्षेत्र के महिला मण्डलों को मतदान से कुछ दिन पूर्व पचास-पचास रूपये दिये गये थे। शैल ने यह समाचार अपने पाठकों के सामने भी रखा था। यह संभावना भी जताई थी कि बजट सत्र के दौरान इस संबंध में प्रश्न भी पूछा जा सकता है। शैल का यह दावा सही प्रमाणित हुआ है। हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा ने प्रश्न पूछा है कि क्या मुख्यमंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि

(क) यह सत्य है कि दिनांक 01 जून से 10 जुलाई 2024 तक देहरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत महिला मण्डलों को कांगड़ा बैंक द्वारा धनराशि जारी की गयी है और (ख) यदि हां तो कितने महिला मण्डलों को कितनी धनराशि जारी हुई ब्योरा महिला मण्डलों के नाम, गांव तथा धनराशि सहित दें।

जब यह प्रश्न जवाब के लिये सदन में आया तो सहकारिता विभाग के प्रभारी मंत्री उपमुख्यमंत्री ने जवाब दिया की सूचना एकत्रित की जा रही है। वैसे सहकारी बैंकों को सहकारिता विभाग से अलग करके वित्त विभाग के अंतर्गत ला दिया गया है और वित्त विभाग का प्रभार स्वयं मुख्यमंत्री के पास है। जब सदन में यह जवाब आया की सूचना एकत्रित की जा रही है तब आशीष शर्मा और पूरे विपक्ष ने यह आरोप लगाया कि जानबूझकर सूचना नहीं दी जा रही है। आशीष शर्मा ने अपने इस वक्तव्य के बाद जो सूचना उनके पास थी उसे सदन के पटल पर रख दिया। आशीष शर्मा द्वारा सदन में रखी गयी सूचना के मुताबिक 27 जून से 10 जुलाई तक क्षेत्र में 13 महिला मण्डलों को पचास-पचास हजार रुपए कांगड़ा बैंक द्वारा दिये गये हैं। इस प्रश्न का सरकार द्वारा जवाब न दिये जाने पर हुई बहस के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी कर दिया है।

देहरा में 10 जुलाई को मतदान था। 27 जून से 10 जुलाई तक क्षेत्र के तेरह महिला मण्डलों को कांगड़ा बैंक द्वारा पचास-पचास हजार रुपए दिये जाने का दस्तावेज आशीष शर्मा ने सदन के पटल पर रख दिया है। सरकार इस दस्तावेज को झुठला नहीं पा रही है। इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि आचार संहिता को अंगूठा दिखाते हुये धनराशि बांटी गयी। चुनाव आचार संहिता के दौरान बैंक प्रशासन द्वारा बांटा गया यह पैसा निश्चित रूप से पूरी चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है। पिछले दिनों हुए हरियाणा और महाराष्ट्र विधान सभाओं के चुनावों में चुनाव आयोग पर कांग्रेस द्वारा गंभीर आरोप लगाये गये हैं। मामले अदालत तक जा पहुंचे हैं । ऐसे में कांग्रेस शासित राज्य में मतदान से कुछ दिन पूर्व कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा इस तरह से महिला मण्डलों को पचास-पचास हजार रुपए देना पूरे चुनाव पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। कांगड़ा बैंक किसी प्राइवेट लाला की दुकान नहीं है। इसका प्रबन्ध निदेशक सरकार द्वारा नियुक्त किया गया कोई एच.ए.एस. या आई.ए.एस. अधिकारी ही होता है जिसे चुनाव आचार संहिता का पूरा ज्ञान रहता है । फिर चुनाव के दौरान इस तरह से बैंक के प्रबन्ध निदेशक के अपने ही स्तर पर ऐसे महिला मण्डलों को आर्थिक सहायता दिया जाना आसान नहीं लगता है। चुनाव के दौरान ऐसे खुला पैसा लेकर कोई नहीं चल सकता है तो एक अधिकारी द्वारा अपने ही स्तर पर ऐसा कर देना संभव नहीं लगता है। इस विवाद पर जिस तरह के ब्यान सरकारी पक्ष द्वारा दिये जा रहे हैं उससे यह मामला और गंभीर हो जाता है।

अब इस प्रकरण पर विपक्ष किस तरह का आचरण अपनाता है इस पर सबकी निगाहें लगी रहेगी। इस प्रकरण के बाहर आने के बाद चुनाव आयोग और प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी इसका कैसे संज्ञान लेता है इस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी।

यह है पैसा देने का प्रमाण

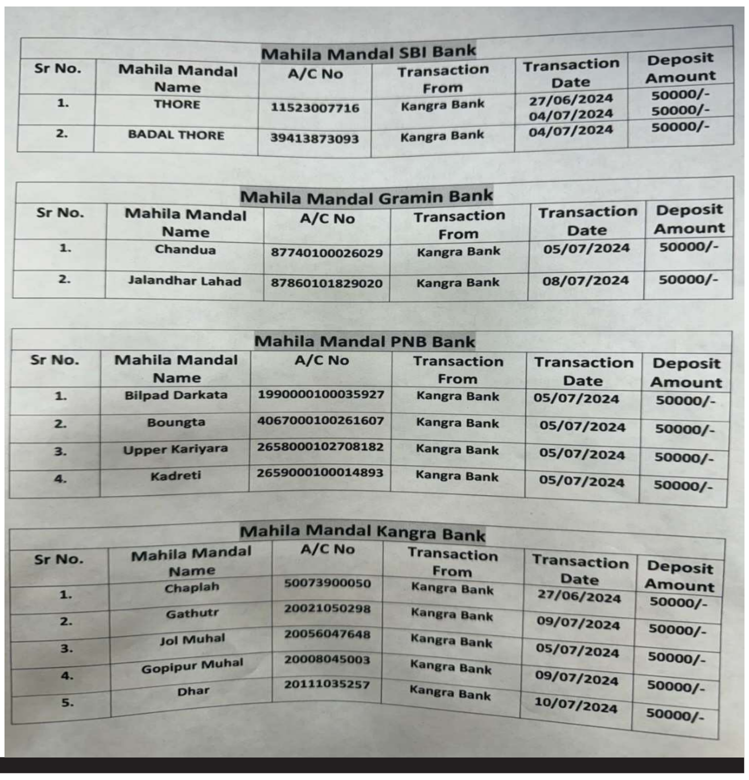

Mahila Mandal SBI Bank

Sr No.	Mahila Mandal Name	A/C No	Transaction From	Transaction Date	Deposit Amount
1.	THORE	11523007716	Kangra Bank	27/06/2024 04/07/2024	50000/- 50000/-
2.	BADAL THORE	39413873093	Kangra Bank	04/07/2024	50000/-

Mahila Mandal Gramin Bank

Sr No.	Mahila Mandal Name	A/C No	Transaction From	Transaction Date	Deposit Amount
1.	Chandua	87740100026029	Kangra Bank	05/07/2024	50000/-
2.	Jalandhar Lahad	87860101829020	Kangra Bank	08/07/2024	50000/-

Mahila Mandal PNB Bank

Sr No.	Mahila Mandal Name	A/C No	Transaction From	Transaction Date	Deposit Amount
1.	Bilpad Darkata	1990000100035927	Kangra Bank	05/07/2024	50000/-
2.	Boungta	4067000100261607	Kangra Bank	05/07/2024	50000/-
3.	Upper Kariyara	2658000102708182	Kangra Bank	05/07/2024	50000/-
4.	Kadreti	2659000100014893	Kangra Bank	05/07/2024	50000/-

Mahila Mandal Kangra Bank

Sr No.	Mahila Mandal Name	A/C No	Transaction From	Transaction Date	Deposit Amount
1.	Chaplah	50073900050	Kangra Bank	27/06/2024	50000/-
2.	Gathutr	20021050298	Kangra Bank	09/07/2024	50000/-
3.	Jol Muhal	20056047648	Kangra Bank	05/07/2024	50000/-
4.	Gopipur Muhal	20008045003	Kangra Bank	09/07/2024	50000/-
5.	Dhar	20111035257	Kangra Bank	10/07/2024	50000/-